बन गई है और पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का सवाल उसने तय कर दिया है जैसे उत्तर प्रदेश मे पन्द्रह परसेंट किया गया है और बिहार ने 26 परसेंट कर दिया है, इसको लेकर इन अराजक तत्वो के साथ मिल कर कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल की पालिसी अख्त्यार करके एक सकट की स्थिति पैदा कर दी है । पटना मे जो कुछ भी हुआ है और कल जो कुछ हुआ है, इसमे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो कुछ हुआ था, वह इसका सबूत है । पिछले तीस साल के अपने शासन काल मे कांग्रेस के लोगो ने पिछडे लोगो की तरफ कोई ध्यान नही दिया और अगर दिया होता तो इस प्रकार की स्थिति पैदा न हुई होती । पिछडे वर्गों की तरफ जनता सरकार ने ध्यान दिया है उसको लेकर कांग्रेस के लोगो ने योजनाबद्ध तरीके से आन्दोलन करना शुरू कर दिया है औ अराजक तत्वो के साथ मिल कर वह ऐसा कर रही है और जनता सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और डिवाइड एड रूल की अपनी पुरानी नीति का अनुसरण कर रही है जो उसको अग्रेजो से विरासत मे मिली थी । जनता सरकार को सतर्क होना चाहिये, चिन्तित भी होना चाहिये । जातिवाद के आधार पर वहा कांग्रेस के लोगो ने अराजक तत्वो मे मिल कर इस प्रकार की अशोभनीय घटनाए कराई हैं । इसकी मै भर्त्सना करता हू और इस सदन को भी करना चाहिये मैं प्रार्थना करता हू कि जनता सरकार इस तरह की घटनाओ को घटने से रोके । जो लोग इस तरह से गडबडी पैदा करने की कोशिश कर रहे है और डिवाइड एड रूल की पालिसी अख्त्यार किए हुए है उनके विरुद्ध जनता ने बहुत बडा फैसला दे दिया था लेकिन फिर भी वे अपनी इन हरकतों से बाज नही आ रहे हैं । तो जनता उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ही, लेकिन सरकार भी ला ऐंड आर्डर बनाये रखने की तरफ ध्यान दे, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करे । बैकवर्ड लोगों को उकसा कर जो डिवाइड ऐड रूल की पालिसी चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी, ऐसी हमारी मांग है ।

12.55 hrs.

GENERAL BUDGET, 1978-79--

GENERAL DISCUSSION—*contd.*

MR. SPEAKER: Now, further discussion on the Budget (General) for 1978-79. Mr. S. S. Das may continue his speech. He has already taken 12 minutes. So, he may please be brief.

श्री एस. सुन्दर दास (सीतामढी) अध्यक्ष जी, कल मैं बता रहा था कि किस प्रकार उपनिवेशवादिता के समाप्त हो जाने के बावजूद भी देश मे पिछले 30 साल से जो अर्थ-व्यवस्था चल रही थी वह उसी प्रकार की अर्थ-व्यवस्था थी जिसमे कि देश का अधिकाश हिस्सा उपनिवेशवाद की तरह हो रहा था, और इस माने मे गाधी जी ने जो चेतावनी दी थी कि जब अग्रेज छोड कर चले जायेगे तो अग्रेजी शासको का स्थान इस देश मे अर्बन सेक्टर ले लेगा । गाधी जी की यह आशका शत प्रतिशत सही निकली ।

मुख्यत दो प्रकार की त्रुटिया अभी तक अर्थ-व्यवस्था मे रही है पिछले शासन मे । एक तो थी आर्थिक योजना का कंसेप्ट, मॉडल था उसकी त्रुटि थी और दूसरी त्रुटि उसके इमप्लीमेंटेशन की थी । अब जहा तक इस नये बजट का सवाल है, जनता पार्टी की आर्थिक नीति का सवाल है उसने आयोजना के मद मे जो त्रुटिया थी उनको दूर करके नई दिशा दी है । इस बजट मे भी, जिसका स्वागत प्रतिपक्ष के भी अधिकाश सदस्यो ने किया है, ग्रामीण क्षेत्रो मे, कुटीर उद्योग मे, लघु उद्योगो मे काफ़ी बडी राशि का प्रावधान किया गया है । तो यह एक शुभ लक्षण है जो कि समूचे एकोनामिक पैटर्न को एक नया मोड देगा । अर्थ व्यवस्था के

[श्री श्याम सुन्दर दास]

साथ साथ एक पोलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमने इनहेरिट किया था, कल माननीय पाई साहब ने उद्धरण दिया था गुन्नार मिर्दल के चेलेंज आफ वर्ल्ड पावर्टी किताब का, उसके साथ साथ चैलेंज आफ वर्ल्ड पावर्टी में एक और चैप्टर भी है सौफ्ट स्टेट का जिस प्रश्न को एशियन ड्रामा में हो पहले भी गुन्नार मिर्दल ने रेज किया था । जनतांत्रिक पद्धति का यह मतलब नहीं होता कि राज्य इतना सौफ्ट हो जाये कि सब तरह के काले कारनामों को पनपने की छूट मिले । दुर्भाग्य से न सिर्फ कांग्रेस शासन ने एक गलत इकोनामिक मौडल दिया, बल्कि कंटायर इंडियन पोलिटिक्स को, पौलिटी को एक सौफ्ट स्टेट बना दिया था जिसके कारण प्लानिंग जो हुआ भी उसका इमप्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो सका । समूची योजना को हम कह सकते हैं, जो पहली सरकार की योजना थी

Planning was not mean for economic growth Rather Planning was meant for perpetuation of dynastic rule and political power

तो इस तरह से वह एक गडबडी थी । जो कसेप्चुअल ऐरर था उसको हमने रैक्टीफाई करने की कोशिश की है । जहां तक इमप्लीमेंटेशन का सवाल है ढांचा वही ढांचा है और इस बजट में या इकोनामिक सर्वे में तमाम क्या क्या प्रशासनिक स्तर पर क्या चेंजेज किये है, इस्टीट्यूशनल चेंजेज और समूचे फ्रेम वर्क में वह सारी चर्चा इसमें दी हुई है कि किस तरह पंचायतों को ज्यादा पावर देंगे । श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं । उसी तरह से कमांड डेवलपमेंट एरिया लोकेट किये गये हैं । इसी तरह से हम समूचे प्लान को उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, जो ट्रेडीशनल ब्यूरोक्रेसी है, उसके बदले एक पैरेलल एजेन्सी, वालेन्टियरी एजेन्सी और स्टेट की कोआपरेशन से इस प्रकार की पद्धति का विकास करने जा रहे हैं । अब सवाल उठता है कि रूरल सेक्टर का जो इतना बड़ा ज्यादा खर्चा हो रहा है, जिस पर पाई साहब ने और सुब्रह्मण्यम साहब ने भी आशंका प्रकट की है कि इन्कीज्ड आउट ले का अर्थ इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन ही नहीं है,

MR SPEAKER How much more time will you take?

SHRI S S DAS Hardly 7 or 8 minutes more

MR SPEAKER· You have already taken 17 minutes Many Members will lose their chance

SHRI S S DAS I will take 5 more minutes

MR SPEAKER I will give you 2 more minutes Please finish

श्री श्याम सुन्दर दास तो वह आशंका भी इस माने में गलत है । प्लानिंग कमीशन के प्रोस्पेक्टिव डिवीजन ने जो रिपोर्ट दी थी, उस समय हमारी सरकार नहीं थी बल्कि पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें भी जो कैपिटल आउट-पुट रेशियो दिया है वह 1974–75 में बढ़ कर 1 41 हो गया । सब से ज्यादा हाइएस्ट रेशियो एग्रीकल्चर में है ।

जहां तक एम्प्लायमेंट का सवाल है, चूंकि कृषि के विकास में हमने दूसरे माडल को अपनाया है, सैकिड प्लान के सम्बन्ध में उस समय जो माडल एग्रीकल्चरल डैवलपमेंट में भी अपनाया गया था, उसमें भी यह था कि अब हम एग्रीकल्चर का दूसरा माडल अपना रहे है, उसमें साइंटिफिक, टैक्निकल नो-हाऊ, इनपुट्स और बैटर मैनेजमेंट दे रहे है । तो माडरनाइजेशन और एग्रीकल्चर के आधुनिकीकरण की दूसरी पद्धति होती है और इस दूसरी पद्धति से एम्प्लायमेंट बहुत ज्यादा होती है । जैसे एक स्टेडी की गई थी कि वेस्ट बंगाल के एक गांव और जापान के एक गांव की, जिसमें यह देखा गया

कि हिन्दुस्तान में एक एकड़ में हम जितने आदमियों को एम्पलाय करते हैं, अगर इस तरह से हम माडरनाइजेशन करते हैं, इनपुट्स, टैक्निकल नोहाऊ और इन्फ्रा स्ट्रक्चर देकर, तो एक एकड़ में चार गुना अधिक आदमियों की एम्पलायमैंट होती है । इस तरह से एम्प्लायमैंट मे भी जैनरेट होगी, आउटपुट भी बढ़ेगा और टैक्सेशन का बेस भी एनलार्ज्ड होगा ।

इन शब्दो के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं गरचे इसमें दो प्रावधान किये गये हैं, एक कोयले और दूसरा बिजली पर कर प्रावधान किया गया है । मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें क्योंकि एक्साइज ड्यूटी से ज्यादा नजर इस आइटम पर है, लेकिन कम-से-कम 15 ऐसे आइटम है जो कि कामन मैन को इफैक्ट करते है और ये दोनो प्रोडक्शन के स्ट्रक्चर को डिस्टार्ट करेंगे ।

PROF R K. AMIN: Mr. Speaker, Sir

MR SPEAKER: Prof. Amin, you will continue after lunch. The House stands adjourned for lunch and will reassemble at 2 o'clock.

13 05 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

GENERAL BUDGET, 1978-79— GENERAL DISCUSSION—*contd.*

PROF. R. K. AMIN (Surendranagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I know the Budget has been variously commented in both in the press as well as in this House. I am also aware of the fact that some people have described it as an inflationary one or it has been said that the Finance Minister has missed his bus or an excellent chance has been missed. Some people have described it as mixed budget or an accountant's budget. Some people have termed it imaginative and growth-oriented. But I would like to set this Budget for the examination of the Members in the right perspective. This Budget is full of very good intentions. There are a number of points about which one can say that the Budget is full of good intentions. And fortunately, the Budget is not so rigid that it cannot be amended on the basis of various criticisms. It is flexible enough and it has good intentions. Therefore, Sir, I would like to highlight the salient features of the Budget and make certain constructive suggestions for the consideration of the Finance Minister so that by the end of April when he comes finally before the House, if he likes, he can make amendments.

Normally, the Budget is judged by three considerations—economy, equity and stability. But in times like this, I would like to utilise the talisman used by Mahatma Gandhi 'what benefits does it bring to the poor'? I have a variety of reasons for taking this view. The Janata Party in the last election by seeking the mandate of the people have pinpointed this problem as the problem number one of India. If we see the trend in the *per capita* income of agricultural population which constitute 72 per cent of the population, it is downward. Now there is a need to arrest and reverse it. We must see that the *per capita* income of the 72 per cent of the population who are depending on agriculture, must rise and that is the criterion which should be applied to the present Budget while judging it. Even all other problems—the problems of social tensions, strikes, gherao, unrest, even the problem of urban poor and slums in the urban areas—are due to the downward trend in the *per capita* income of the agricultural population. That is why, I would like to judge the Budget from that point of view. The

[Prof. R K. Amin]

important question to be asked is how do we increase the income of this sector? Now to my surprise, Mr T. A Pai and Mr Subramaniam and others have referred to the poverty problem They were dealing with it for the last six or seven years I find from the Economic Survey that even the per capita consumption of essential commodities like edible oil, cereals, kerosene and things like that has been coming down since 1971 Although they were aware, as he said, Mr Subramamam put forth some facts that it was he who defined what was poverty, it was he who said that poverty should be accepted as a main objective or mam problem in the Fifth Five Year Plan All these things he said But if you see the Economic Survey, you will find that so far as poor people are concerned, so far as their goods and services are concerned, there was a fall throughout six years period and that is why it is very necessary to examine it from that point of view In order to do that I find that there are four factors of the economy which are problem sectors The first is the agricultural sector which is badly hit Unless and until budget does something in order to bring more and more capital and more and more income to the agricultural sector the injustice done during the last 30 years to this sector cannot be rectified The second is the mamoth growth of the public sector which takes away about 60-65 per cent of the investible resources of the country and yet does not contribute commensurate to their use of the investible resources The third is the sick and unviable industrial sector The fourth is the corrupt sector where black money or the paralled economy let me put it, as has been described by many people, is working

The budget must examine these four problem sectors and should deal with them in the Indian economy Let me take the agricultural sector There are two difficulties with the agricultural sector One is that there is shortage of capital The per capita investment in agricultural sector is the lowest Now the budget should see that it is rectified I am happy to note one thing which the budget has done for which the Finance Minister's name will go down in history and that is allocation that he has made for the dairy development That is exactly the field in which the investment in agricultural sector has increased, that is exactly the field in which the employment will increase considerably and that, is exactly the field in which the production will be increased and the income of those poor people will also be increased and the allocation is so sufficient and so big that it is bound to make an impact on the rural economy For this alone, I would say that the Finance Minister should be congratulated

I would like to draw his attention to the agricultural sector and say that the agricultural sector is subjected to various penalities the penalty being that its own products are not allowed to be exported Now if at all any impediments are created they are created in the field of agriculture May be the essentiality bogey may be coming in the way Onion is most essential, therefore let us stop sending them abroad Otherwise the price will go up But we do not realise this fact that when onions and potatoes will be stopped from going abroad, the prices will fall down and nobody will grow onions and potatoes next year As you know there is always a time lag in the production of all agricultural commodities The crop has come in the market You can say that you will not allow it for export The prices will go down The commodity will be available at a cheaper price Now you will be happy that the prices have come down But the result will be that next year nobody will grow that commodity and Government does not ensure simul-

taneously while it is banning the export of it that how the production of that commodity will be increased? Therefore, on sugar, on gur, on potatoes, on onions and other things whatever impediments have been created must go away.

In order to accelerate the agricultural production, in the budget three things are very important—irrigation, power and extension services. Now on these three things, I would request the Finance Minister to reconsider his proposals. You take the irrigation first. There has been only 13 per cent increase in the allocation of resources, although he has said that the irrigation potential which will be available next year will be increased by about 40 to 45 per cent. I fail to understand how, by allocating only 13 per cent more of the resources, you could have the supply increased by 40 to 45 per cent. Therefore, the allocation should be increased....

AN HON. MEMBER: Continuing schemes.

PROF. R. K. AMIN: If you only concentrate on schemes which are just fructifying this year and do not spread them out evenly as is necessary, then there may be some lopsidedness; next year, he will have to face this problem; that is why, to avoid that lopsideness, the allocation should be increased.

He should also increase the allocation for power. He should also make one thing clear. Whatever may be the additional generation of power, fifty per cent of that must be utilised for agriculture; rather, fifty per cent of that should be made available for utilisation in agriculture. Otherwise, what will happen is this, i.e. What happened in the case of cement? During the last 30 years, the cement production has increased five times, yet, cement is not available to the rural people. Now, generation of power will increase that much, but it may not be availabe to the rural people. I would, therefore, suggest to the Finance Minister that he must see that, whatever additional power comes into existence, a good deal of that, about fifty per cent of that, must go necessarily for the use of agriculture.

As regards public sector, I would like to make a hint to the Finance Minister. For the last several years, we have talked about it. We allocate 60 to 65 per cent of our investible resources for public sector. But we do not get adequate return from it, may be due to mismanagement or wrong allocation of resources or whatever it is. Is it not worthwhile for the Finance Minister to consider winding up some of the public sector units like the STC and MMTC or at least consider restricting their activities? Is is not possible for the Finance Minister to raise some portion of these investible resources from the public and get them registered with the stock market, so that by quotation the signal is given to the Government right in time? Today what happens is that evil grows there so much that by the time the attention is drawn, it becomes too late to mend it. If it is on the stock market, then immediately the attention is drawn because the quotation may come down and in time, amendment can take place in the public sector. This is a suggestion which I would like to make to the Finance Minister for his due consideration.

In regard to several industries, I have to make some suggestions when I come to the taxation part.

One aspect to which I would like to draw the attention of the Finance Minister is the sale of gold which he has accepted. Here I must congratulate him because, so far, the Morarjibhai's effect was working. It was Morarjibhai who was responsible for introducing the Gold Control Order. It was based on the Keynesian theory that gold is a barbaric relic of the past; it is unproductive investment and therefore should not be encouraged. Now, the world over, it has

[Prof. R. K. Amin]

been accepted that it is an investment instrument It has also been accepted as a device or hedge against inflation—as a non-depreciating aspect. Now it is controlled by the whims and caprices of the managers of the monetary aspects of the economy Now that the Finance Minister has accepted importing gold and selling it from whatever stock he has, it has removed the Morarjibhai's effect It has been accepted that it is not the Reserve Bank which will decide everything in this matter, not even the Finance Minister, the other factors will also play their part Although it is an unproductive investment, because the people have preferred it, this concession has been allowed That is a great departure from the earlier policy decision which had been taken for which I must congratulate the Finance Minister I must say that the Finance Minister could do this job also simultaneously Silver is being demanded at a higher price abroad He can export silver Whatever silver he export, he can import gold of that value so that our gold stock, a valuable commodity, is not affected in our country And the difference between the international price and domestic price is so big I would suggest that, by indulging in this trade, probably the Finance Minister will be able to make good some portion of deficit financing —the gap of deficit in the budget—by having transactions in gold I propose that he should start from the very next day It is not difficult to do it The Reserve Bank can invite tenders say of 'Five thousand tolas of gold' The moment tenders are received, immediately a cable could be sent to the London Market "Buy on our behalf 5000 tolas of gold" Why should he waste any time in order to do this? He should do it from the very next day He knows very well that the day on which he announced this policy the gold prices started coming down in the market Now it is returning to the same level because an impression has been created that Government will take a long time or will do it in such a manner that its effect will be wiped out So, may I request the Finance Minister to take action as early as possible?

Now, regarding deficit financing, my friends opposite had talked about ten times more of deficit financing and some people have said 'Simply because it is deficit financing, inflation will take place" Let me tell you that last year also it was Rs 884 crores of deficit financing When he said, 'I will draw it on my foreign exchange reserves with the Reserve Bank' does not necessarily nullify the true deficit financing of the Government It was 885 crores and has turned out to be 975 crores but the gap is not as much as it used to be when the Congress was in power There if we take a five years' average deficit financing as estimated was Rs 175 crores but the actual deficit financing turned out to be on an average Rs 800 crores The estimated figure was 175 and the actual was 800 But here if you examine the statistics, it was 884 last year and it has now turned out to be 975 and it is going to be 1050 Now from that please don't conclude that inflation is going to take place I would not even like the Givernment to think that although the deficit financing was Rs 884 crores and Rs 975 crores, the prices are stable No, nothing of the sort Prices are stable because the weather was very good and agricultural production has increased Moreover, those two or three lakhs of people working in the Middle East had sent during last year, Rs 2400 crores to us These figures are not available, but I learnt from these people that it was Rs 2400 crores Now that has kept your prices down, that has kept your inflationary effect down, although there were many other forces which might have led to inflation This year also, you must notice that your deposit credit ratio is lower There is a possibility of increasing credit by the commercial

banks, but they have not been able to do so because of the industrial situation. Money is sifting: money is not on-wing. The velocity of its circulation is lower. But it is likely to be higher at any time. So, the potential is there, if there is good management on the part of the Government—and there is likely to be good management on the part of the Government because there are so many slips between the cup and the lip e.g. foreign aid might be increased and still those people—our Indian friends working in the Middle East—might come to our rescue and might send Rs. 3000 crores this year. Then your p oblems are over. It may be 1050 crores or 1100 crores or 1200 crores of deficit financing it will make no difference But may I make a request to the Finance Minister—I did it last year in the Budget as well as in the Consultative Committtee when I said "Why do you bother about such index numbers, wholesale, retail and consumers? What you should be concerned with is the index number of poor people" Evolve, by sitting with other Members of the Opposition, an index number of goods and services which poor people require or poor people use and see that this index number is stabilised Don't bother about anything else because prices, on the one hand, and income, on the other, are closely related; prices alone are not to be taken into account

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already taken twenty minutes, please conclude now.

PROF. P K AMIN: About unemployment, I would like to draw the attention of the Finance Minister that here in this House we have discussed the problem of unemployment many times. The idea of work-places has been suggested by no less a person than the Prime Minister. I thought that it will come in the budget this year; it has not come in the budget. It must be started. In so far as the unemployment is concerned, the scheme of work-places can act as a lender of the last resort. If you go to the work place at 9.00 in the morning, it will ensure that you will be given employment and you will be given Rs. 5 as wages. It will help and increase the income of seventy two per cent people who are considered to be the poor people depending on agriculture. This should have been started right now without any delay.

I also congratulate the Government on a beginning for a cheap money policy The interest rate policy followed so far was encouraging the financial investment, not industrial investment. Everybody was eager to put in the savings account and not invest in the industries. Now that the cheap money policy will be adopted—still more and still further he should do it—it would encourage industrial development and the savings put in the banks and not being used would be discouraged.

Before I sit down, I would like to say a few things more As far as the direct taxes are concerned, the Finance Minister could have straightway given exemption for income-tax purposes upto Rs. 10,000. Whatever woolliness was there last year could have been avoided this time. He should have reduced the Corporation tax also. Only the rich people are the share-holders of the Corporations If that tax is removed or lowered down, the middle income group people also could be the shareholders and can participate in this and whatever ills are there in the Company Law could have been avoided. Further, he could have dispensed with the wealth-tax, estate duty and gift tax and instead imposed the death duty. At the time of death, take away whatever amount of wealth you want. Let the man earn and spend but at the time of death when the wealth passes on to somebody else, you take the greater portion of it. Probably, that will give greater incentives.

I have a lot to say, but as you are hurrying me up, I would say one more thing about the indirect taxes. To tackle the corrupt sector, the de-

[Prof R K. Amin]

monetisation is not the way Sweden allowed investment of money in the housing and they said, We will not ask a single question from where you get the money You are very eager to increase the rural development Why don't you say these are the areas, the rural areas, where if you start such industries, we will not ask you from where you got the money You will see that very soon, the rural development will take place With all the incentives being given to the corporate sector, the rural development will not come Even if you demonetise hundred-rupee notes, you will not be able to do it But this is the thing which you can do it

The Finance Minister has appointed two or three committees Quite recently he has appointed Dagli Committee He could have done it twelve months ago Why should he wait for 12 months? This Committee also consists of those people who are not committed to a particular ideology or particular direction which the public wants us to take In the Committee, you could have put some suitable people

In the end I would like to give five or six suggestions You should appoint an Income and Price Board There should be a Protection Board for deciding what level of protection should be given to the industries There should be a Tripartite Commission of Labour Management and Government to decide the wage and income policy A Rural Development Ministry should be constituted separately as also an Economic Coordination Ministry

Lastly I would say that the Finance Minister has got a golden opportunity to put the economy on the right keel I would request him to rise to the occasion, take guts in his hands, make an imaginative bold effort and change the structure of the taxation expenditure and the economy in such a way that the aspirations of the people which have been depicted in the last elections are achieved and the course of the last thirty years would be reversed He should give a new turn to the economy so that his name goes down in the history in golden letters.

SHRI S R DAMANI (Sholapur): I rise to speak on the Budget for 1978-79

This is a Budget which has not come up to our expectations It was expected that there will be some concrete proposals for checking inflation but we find that all the proposals of the Finance Minister will only add to the inflation

As my colleagues, Shri Subramaniam and Shri Pai have already spoken about the taxation proposals, I will not like to deal with them But it is a fact borne out by the Economic Survey presented to the House

> "The most notable feature of the economic situation in 1977-78 was the absence of any serious constraint on economic growth In the past shortages of food and foreign exchange have been the two major factors which have acted as a brake on economic growth"

An experienced economist and administrator as Mr Patel is it was expected that the economy will be strengthened by his budget and there will be a further growth and prices will go down But I am sorry to say that things have not come upto expectation

The Finance Minister feels that a 5 per cent growth which has been achieved during this year is satisfactory According to me, in the circumstances when our food production has reached the target of 120 million tonnes as it was in 1975-76, if you compare the performance, I think it is lacking in many directions In 1975-76 when the foodgrain production was 121 million tonnes, what was the rate of growth? It was 8 5 per cent but here it is only 5 per cent

Increase in industrial production—11.4 per cent whereas this year it is only 4 per cent. I doubt whether by the end of the year even this 4 per cent will be maintained or not. Secondly, electricity generation—an increase of 13.5 per cent in 1975-76 over the previous year increase of 5.2 per cent. Now in 1976-77 the increase was 11.8 per cent and this year it is only a 2.5 per cent increase. So from 11 8 per cent it has come down to 2.5 per cent. Take the wholesale prices. In 1975-76 when the Congress Government achieved a production of 121 million tonnes, there was a minus growth of 1.1 per cent and in 1976-77 there was a nominal rise of 2.1 per cent. But this year it has gone up by 6.6 per cent more than 3 times. When the production was lower by 10 million tonnes, the rise was only 2.1 per cent but when the production has gone up by 20 million tonnes, the rise is 6 6 per cent

Now, coming to exports, in 1972-73 it went up by 20 per cent. In 1974-75 it increased by 21 per cent and in 1975-76 there was an increase of 27.2 per cent and this year the increase is only 9 3 per cent In 1976 imports were down by 3 6 per cent. This year they have risen by 3.8 per cent.

Cement which was being exported, we have to import

Aluminium, we have to import. All the items which were in surplus were being exported. This year we have to import them The result is that our import has gone up by 3 8 per cent. It was previously down by 3 6 per cent.

Circulation of notes has increased by Rs. 950 crores. I am surprised that in the last para of his speech the Finance Minister has said:

> "The economic situation of the country is exceptionally favourable at present for a bold step forward. This Budget is such a step".

I do not understand how it is a bold step when in every respect there is a decline. Therefore, something has not gone well. It requires re-thinking.

I would like to know from the Finance Minister—how many people are below poverty line? How many have been upgraded and taken above the poverty line? How many jobs have been created? How many have been given gainful employment in industries?

It has been mentioned in the Economic Survey that there is lack of demand and, therefore, production has not increased. May I know why is the lack of demand there? I think it requires re-thinking otherwise the situation will become difficult.

I would like to point out regarding compulsory deposit. Compulsory deposit was introduced in 1974 when there was inflation. Prices were going up This step was taken to have a check on prices. At that time there was lack of production. Now, we thought that the Government was going to withdraw compulsory deposit scheme because this will not help. I thought because of lack of demand production was going down. I think Government will reconsider the measures that have been taken in this connection. This Budget is neither production-oriented nor is it employment-oriented. It is an inflationary budget, and it is not up to the expectations. And, therefore, I think, the hon. Finance Minister should reconsider these proposals, and give some relief so that production can increase and saving can be effected.

With these words. I once again request him to reconsider these proposals. I opppose the Budget.

श्री एच० एल० पटवारी (मंगलदाई): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्री का भाषण देखा और माननीय सदस्यों के भाषण भी मैंने सुने। मेरे कुछ विचार हैं। पहला मेरा विचार यह है कि सदन को ऐसा एक कलेक्टिव सुझाव देना चाहिए वित्त मंत्री को कि हम

[एच० एल० पटवारी]

कितना रुपया तक देशवासियो से कर के रूप मे इकट्ठा करेगे । यह एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, वरना एक वित्त मत्री आएंगे, टैक्स लगाएगे, फिर दूसरे वित्त मंत्री आएंगे, उन के अपने अलग विचार होगे । इस से देश की अर्थ-व्यवस्था अस्थिर हो जाती है इसीलिए, उस को स्थिर करने के लिए हम कितना रुपया इकट्ठा करेगे करो मे और उसका वितरण कैसे होगा उस की कुछ नीति निर्धारित कर दे । उस को कैसे खर्च करेंगे यह वित्त मत्री का काम होगा ।

इस बजट मे हम ने देखा है कि 15 हजार करोड तक की आमदनी टैक्स और दूसरी चीजो से निकाली गई है । मेरा पहला सुझाव यह है कि इस मे से कम से कम 50 प्रतिशत पैसा अलग रख देना चाहिए और उस को ऐसी चीजो पर खर्च करना चाहिए जो हमे वापसी दे, अर्थात् प्रोडक्टिव स्कीम्स मे वह 50 प्रतिशत खर्च होना चाहिए । दूसरा सुझाव यह है कि 5 प्रतिशत रिजर्व फड मे जमा कर दे । बाकी 45 प्रतिशत मे से ऐग्रीकल्चर पर जो वित्त मत्री ने बढाया है यह तो ठीक है लेकिन ऐग्रीकल्चर की मद पर अगर हम देश की अर्थ-व्यवस्था को निर्भर करेगे तो हमारा देश बनने वाला नही है । ऐग्रीकल्चर सेक्टर पर देश के 40 प्रतिशत लोगो का एम्प्लायमेट होना चाहिए जो अभी 74 प्रतिशत इस मे लगे हुए है । ससार के जितने बडे बडे देश हैं सब ने इसी प्रकार किया है । यूनाइटेड स्टेट्स मे 1890 मे 43 प्रतिशत लोग ऐग्रीकल्चर मे एम्प्लायड थे । उस को घटा कर उन्होने 5 प्रतिशत किया । आस्ट्रेलिया मे 26 प्रतिशत थे, उस को घटा कर उन्होने 8.1 किया । ग्रेट ब्रिटेन मे 15 प्रतिशत लोग ऐग्रीकल्चर मे एम्प्लायड थे, उस को कम कर के 2 प्रतिशत किया । इसी तरह से बेल्जियम मे 18 परसेंट से घटा कर 4 परसेंट किया । ससार के सारे देशो ने ऐग्रीकल्चर से कन्वर्ट किया दूसरे कामो मे । हमारे देश मे पहले 1800 सेनचुरी में 74 परसेंट एम्प्लायमेट ऐग्रीकल्चर मे था । आज करीब 72 परसेंट है । करीब करीब एक ही है । उस से पहले 1700 शताब्दी मे 40 परसेंट था । उस समय देश सुखी था । लेकिन जब ऐग्रीकल्चर मे बढाया तो देश गरीब हो गया । तो मेरा यह सुझाव है कि ऐग्रीकल्चर पर ज्यादा बोझा न पडे और उस की जगह पर बोकेशनल और दूसरी मदो मे हमारे बजट का पैसा खर्च हो । वित्त मत्री इस पर सोचेंगे ताकि देश के लोगो को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके ।

मेरा दूसरा प्वाइट यह है कि आज हम जो पैसा खर्च करेगे उसका फायदा 31 परसेंट या 34 परसेंट लोगो को मिलेगा—यह पर्सेंटेज का आधार नही होना चाहिए बल्कि देश के सभी लोगो को उसका फायदा मिलना चाहिए । मेरा कक्रीट सुझाव है सबसे पहले कि आप जब तक देश के ग्रामो को पुनर्सघटित नही करेगे, रिआर्गेनाइजेशन आफ विलिजेज नही करेगे तब तक हमारे देश की आर्थिक अवस्था सुधर ही सकती है । वर्तमान मे जो 6 लाख गाव इस देश मे है उनको घटा करके आप 20–20 या 15–15 हजार की आबादी के बडे बडे गाव बनाये । इस प्रकार घरो को बनाने मे जो खर्चा आयेगा उसके लिए आपको योजना बनानी चाहिए । आज जो भी सुविधाये शहरो मे मिलती है वही सुविधाये देहातो को भी उपलब्ध करानी चाहिए । इस प्रकार से ही हम एक यूनिफार्म सोसायटी इस देश मे बना सकेंगे । इसके करने मे एक ओर तो हमारा खर्चा लगेगा लेकिन दूसरी ओर स्कूलो, रास्तो और दूसरे मामलो में रेकरिंग खर्चा हम घटा सकेंगे । आज राज्यों मे जो स्कैटर्ड गांव बसते है उसका कोई बेनिफिट किसी को नही होता है । यदि गांवों का सही रूप रहेगा तो कभी भी

आप गांव वालों को कोई सुविधा नहीं दे पायेंगे।

मेरा तीसरा प्वाइंट यह है कि हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में पहले जो पोलिटिकल किग्ज थे जिनका बोल बाला था उनको हम ने मिटाया। जिनको हम क्षेत्रीय कहते हैं, जिन्होंने सामंतशाही के नाम से हरिजन आदिवासी लोगों के पोलिटिकल राइट छीन लिए थे उसको हमने मिटाया, यह तो ठीक है लेकिन इस देश मे हमने एकोनामिक किंग बना दिए। पोलिटिकल किंग्ज की जगह पर हमने एकोनामिक किंग्ज बना दिये जोकि ज्यादा डेजरस हैं। इस देश के आदिवासियों के दिल मे यह डर पैदा हो गया है कि उनका शोषण करने के लिए एकोनामिक किंग्ज बना दिए गए हैं। एकोनामिक किंग्ज जो हैं वे पोलिटिकल किंग्ज या सोशल किंग्ज से भी ज्यादा डेजरस है। इसलिए मेरी माननीय पंत्र बहोद जी से प्रार्थना है कि जब तक आप इन एकोनामिक किंग्ज को सस्पेंड नही करेंगे तब तक इस देश की एकोनामिक व्यवस्था सुधर नही सकती है। मेरा सुझाव है कि आज से और अभी से, जितने भी एकोनामिक किंग्ज हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। उनके रहने का जो तरीका है उसको सीमित करना चाहिए। उनको इस तरह की छूट नही देनी चाहिए कि एक लैट्रिन बनवाने पर 25,000 रुपए खर्च करे और चार-चार गाड़िया रखें। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था नही रहने देनी चाहिए। अगर आप तुरन्त एकोनामिक किंग्ज पर अंकुश लगायेंगे तभी इस बजट का फायदा गरीब किसानों तक पहुंच सकेगा।

इसके अतिरिक्त जो हमारी शिक्षा नीति है उसमे भी सुधार करने की आवश्यकता है। इस समय जो देश में शिक्षा व्यवस्था है उसके नाम पर हम देश में विभ्रांत वातावरण पैदा कर रहे हैं। एक तरफ हम पैसा खर्च करके कुछ लोगों को पढ़ाते हैं, एक के ऊपर तीन चार लाख रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ जब उनको एप्वाइंट करके हम एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं तो वे हमारा शोषण करते हैं और फिर ब्यूरोक्रैट्स के नाम पर हम उनको एब्यूज करते हैं। फिर हम उनको पढ़ाते ही क्यों हैं और इस प्रकार की शिक्षा ही क्यों देते हैं? इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ब्यूरोक्रैसी पैदा ही न हो। हम ऐसे लोगों को एप्वाइंट करें कि उनको ब्यूरोक्रैट कहना ही न पड़े। देश के डेवलपमेन्ट में उनका भी हिस्सा हो। केवल इस सदन में ब्यूरोक्रैट्स के खिलाफ बातें कह कर हम उनको मिटा नहीं सकते हैं। जब हम चपरासी एपाइन्ट करते हैं तो क्वालिफिकेशन्स फिक्स करते हैं, जब क्लर्क एपाइन्ट करते हैं, तो क्वालीफिकेशन्स फिक्स करते हैं और जब अफसर बनाते हैं, तो क्वालीफिकेशन्स फिक्स करते हैं लेकिन इन अफसरों को चलाने वाले जो पोलीटिशियन्स हैं, उनकी कोई एज-लिमिट नही है। 35 साल का तो वह आएगा लेकिन 100 वर्ष का भी वह हो सकता है चाहे वह एफीशियेन्ट हो या न हो। इस वक्त 100 वर्ष वाले पोलीटिशियन्स भी हुकम देने वाले बन सकते है। इसलिए मै यह चाहूंगा कि उन के लिए भी कोई एज लिमिट होनी चाहिए और क्वालीफिकेशन्स भी निर्धारित करनी चाहिए। जो अफसरों को चलाएंगे, वे एफीशियेन्ट हों और सही गाइडेंस उन से मिले, इस के लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए भी क्वालीफिकेशन्स निर्धारित होनी चाहिए। इस के अलावा ज्यादा एज वाले लोग भी पार्लियामेंट मे न आए और शासक न बनें। मैं यह भी चाहूंगा कि मंत्री जी बनें उन का पहले एग्जामिनेशन होना चाहिए कि वे एफीशियेन्ट है या नहीं। अगर वे एफीशियेन्ट नही हैं, तो ब्यूरोक्रेट को क्या हुक्म देंगे। मै चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करें कि जो सिस्टम इस समय है उस में चेन्ज आए ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एफीशियेन्ट हो जाए।

अब प्रश्न यह है कि कुछ लोग तो हमेशा ही शासन में बुराई देखते हैं। कुछ लोग

[श्री एच० एल० पटवारी]

अच्छाई भी देखते हैं और अच्छे सुझाव देते हैं लेकिन जो लोग हमेशा बुराई देखते हैं, इस से काम चलने वाला नहीं है । हम अच्छे सुझाव क्या दे सकते हैं, इस के लिए हमें काम करना चाहिए ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सब से बड़ी बेचैनी आज यह पैदा हो रही है कि एक तरफ तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी 6 लाख आदमियों की नसबन्दी कराते हैं और दूसरी तरफ 12 लाख नान-इन्डियन्स भारत में आते हैं । जब बाहर से इतने आदमी यहां आएंगे और यहां के आदमियों की नसबन्दी करेंगे तो बैलेंस आफ पापुलेशन कैसे होगा । यह कितनी गम्भीर बात है, इस को सारे सदन को सोचना होगा । जब हम जनसंख्या को कम करने की नीति को मानते हैं तो बाहर से जो नान-इन्डियन्स आते हैं, उन की भी हम देखें । मैं जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर यह बात नहीं कह रहा हूं । उगान्डा से आदमी निकाले गये । सीलोन में भी ऐसा ही हुआ । बर्मा से भी लोग आए और पाकिस्तान से भी बंगाली निकाले गये । इस तरह से इन्डिया में आप नानइन्डयन्स को कैसे एलाऊ करते हैं ? किस लिए ? इस पर भी गम्भीरता से विचार होना चाहिए ।

आज हमारी शिक्षा नीति में कोई कोआर्डीनेशन नहीं है । प्राइमरी में बुनियादी काम करने की बात सिखाते हैं, सैकेन्डरी में सिखाते हैं क्लेरीकल काम और फिर कालेज में जा कर अपनी चोआयस के मुताबिक सबजेक्ट्स चुनते हैं । इस तरह से आपस में कोई कोआर्डीनेशन नहीं है । प्राइमरी में एक किस्म का काम सिखाएंगे । सैकेन्डरी में दूसरे किस्म का और कालेज में अपनी चोआयस के मुताबिक चलेंगे । इस तरह से तीनों में कोआर्डीनेशन कैसे होगा । यही नहीं हो सकता है । इसलिए शिक्षा का प्राइमरी से ले कर आखीर तक एक सामंजस्य होना चाहिए ताकि शिक्षा में आकर्षक हो सके । शिक्षा जिन्दगी का एक साधन है, शिक्षा से मनुष्य अपना जीवन बना सकता है लेकिन आज की जो शिक्षा है, वह विद्यार्थियों में एक बेचैनी पैदा कर रही है ।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन (बालाघाट): हर साल नई किताबें बनती हैं ।

श्री एच० एल० पटवारी : जी हां । हर साल नई किताबें बदली जाती हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप तो टीचर्स की संस्था के प्रेसीडेंट हैं ?

श्री एच० एल० पटवारी : मैं प्रेसीडेंट हूं । इसलिए मेरा सुझाव है कि शिक्षा की एक स्थिर नीति होनी चाहिए । अभी मैं गाजियाबाद में भाषण दे कर आया हूं । 26 लाख टीचर्स सरकार के साथ हैं । देश के निर्माण के लिए 26 लाख अध्यापक और 10 करोड़ बच्चे हमारे साथ हैं लेकिन हमारी नीति सही होनी चाहिए कि किधर हमें जाना है । इसीलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा के मद में एक स्थिर नीति होनी चाहिए । मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने शायद मान लिया है कि शिक्षा को कान-करेन्ट लिस्ट में रखेंगे । इस से देश के अध्यापकों में बड़ा संतोष है कि जनता की सरकार ने जनता का ध्यान रखा है । एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि शिक्षा एक नेशनल पालिसी के अन्तर्गत दी जाए । अध्यापकों के लिए एक वेज बोर्ड होना चाहिए । प्राइमरी शिक्षा के लिए एक प्राइमरी ग्रांट्स कमीशन होना चाहिए । प्रशासन में नियुक्तियों के लिए न्यायपालिका की तरह एक शिक्षा-पालिका बने जिससे नियुक्तियों में राजनीति का प्रभाव खत्म हो । जब हम ऐसी व्यवस्था करेंगे तभी शिक्षा में सुधार होगा ।

हमारे देश में कर लगाने की व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की थी। इससे पहले हमारे देश में कर लगाने की व्यवस्था नहीं थी। (व्यवधान) अब कर लगायें या न लगायें यह तो सदन की बात है लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जितना भी पैसा हम कर रूप में लेते हैं वह सब जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। आज एक सरकारी कर्मचारी का खर्च तीस आदमियों को वहन करना होता है। मेरा सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह भी सुझाव है कि कम से कम तीस प्रतिशत कर्मचारियों को वन विभाग में लगाया जाए। इसके लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए ताकि उन लोगों से कुछ-न-कुछ काम लिया जाए। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी को भी लिखा है। हमने उनको लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को काम पर लगाना चाहिए। यह न हो कि एम्प्लाएमेंट फार एम्प्लाएमेंट सेक हो। अब इन सरकारी कर्मचारियों को कैसे काम पर लगाया जाए इसकी जिम्मेवारी वित्त मंत्री जी पर है।

गावों में अनएम्प्लाएमेंट है। मेरा सुझाव है कि गावों में एक-एक यूथ को दो-दो गायें दे देनी चाहिए जिससे वे दूध का उत्पादन कर सकें। इससे दूध भी अधिक पैदा होगा और उन लोगों को काम भी मिल जाएगा।

रास्ते या सड़कें बनायी जाती हैं, मेरा सुझाव है कि हमारे रोड्स कम फिशरी परस्पेक्टिव्ज होने चाहिए। इससे हमें लाभ होगा।

हम घास लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। इन पर काफी पैसा खर्च करते हैं। मेरा सुझाव है कि हमें शेड कम फ्रूट्स ट्रीज लगाने चाहिए।

हम काटेज इंडस्ट्रीज का जो अर्थ लगाते हैं मेरे विचार में वह सही अर्थ नहीं है। हाथ से जो भी काम होता है उसको हमें काटेज इंडस्ट्रीज मान लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बनिये लोग उसका फायदा उठाते हैं। देश में जो भी काम हाथ से किया जाता है उसे काटेज इंडस्ट्रीज मान लिया जाना चाहिए।

मैं डबल प्राइस सिस्टम के हक में नहीं हूं। इससे ब्लैक मनी पैदा होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें डबल प्राइस सिस्टम को बिल्कुल हटाना चाहिए। विद ड्यू रेस्पेक्ट टु दी फाइनेंस मिनिस्टर, मैं निवेदन करता हूं कि अगर यह नहीं किया गया तो हम अनशन करेंगे।

हमारे कालेजों और यूनिवर्सिटियों में एग्रीकल्चरल रिसर्च की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश की पैदावार बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्वी अंचल में पिछले तीस सालों में कोई विकास नहीं हुआ। वह क्षेत्र बिल्कुल अविकसित रहा है। हमारे यहां पानी है, नदियां हैं लेकिन वहां के पानी को जमा करके 12 महीने किसानों को देने की कोई व्यवस्था नहीं है। भाखड़ा नंगल हीराकुण्ड आदि आपने बनाए हैं। असम में इतनी नदियां हैं लेकिन फिर भी उनका पानी जमा करने की कोशिश नहीं की गई है। अगर ऐसा किया जाए तो सारे भारत के लिए हम वहां अनाज पैदा करके दे सकते हैं।

15 hrs.

शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज का हमारे यहां कोई प्राबलैम नहीं है। यह एक क्रियेट किया हुआ प्राबलैम है। सब लोग हमारे यहां भाई भाई की तरह रहते थे। लेकिन राजनीति के चक्कर में इस प्राबलैम को बढ़ावा दिया जाता है। मैं समझता हूं कि प्यार और मुहब्बत से इस समस्या को हल किया जा सकता है।

श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में जो जो फिगर्ज दी गई थीं उनके आधार पर मैं

[श्री एच० एम० पटवारी]

कहना चाहता हूं कि हमारे देश मे एक करोड़ के करीब बेगर हैं जिनकी आमदनी एक रुपया दस पैसे होती है। बैगरी देश के लिए महापाप है। इस पाप को मिटा देना चाहिये, एक दम मिटा देना चाहिये। भिक्षा मागना सबसे बड़ा पाप है। इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये।

जो पेंशनर हैं, उनकी सर्विसिस को भी आपको युटिलाइज करना चाहिये, यही अंतिम बात कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हू।

श्री कल्याण जैन (इदौर) : मैं इस बजट का समर्थन करता हू और आने वाले पाच सालो तक वोट से समर्थन करता रहूगा यद्यपि वह बजट इदिरा और नेहरू की लीक पर चलते हुए चौधरी चरण सिंह और जनता पार्टी के घोषणा पत्र की छाप मात्र है।

यह खुशी की बात है कि जनता पार्टी ने सारे देश मे एक ऐसा वातावरण जो अच्छा है पैदा कर दिया है कि जनता पार्टी कृषि, कुटीर उद्योगो, ग्रामीण उद्योगो के ऊपर जोर देगी। मेरा सभी माननीय सदस्यो से निवेदन है कि भारत मे क्या टैक्नोलोजी होनी चाहिये उसके बारे मे कम से कम वे अपनी दृष्टि बनाए। रूस औ अमरीका के समान भारत मे टैक्नोलौजी नही हो सकती है। रूस मे एक वर्ग मील मे मुश्किल से सात व्यक्ति रहते हैं, अमरीका मे बीस बाईस रहते हैं लेकिन भारत मे चार सौ रहते हैं। साथ ही हमारे यहा पूजी की कमी है जबकि उन देशो मे इसकी बहुतायत है। इस वास्ते उनके समान भारत मे तकनीकी को नही अपनाया जा सकता है। यह सबसे बडा दुष्परिणाम जनता पार्टी को पिछली हकूमत से जो तीस साल तक राज्य करती रही हैं, विरासत मे मिला है। उसी का यह परिणाम है कि भारत मे चार करोड़ के करीब लोग बेकार हैं। अर्द्ध-बेकार हैं, गुंडागर्दी है, सट्टा है, बेरोजगारी है, ला एण्ड आर्डर की समस्या है। इन सब का हमें मुकाबला करना है। बजट के द्वारा जो एक आशा लोगो मे जगी थी वह थोड़ी निराशा मे परिवर्तित हो गई है। हजार, दस हजार, पाच हजार के नोटो का आपने प्र चलन बन्द कर दिया था और उससे भारत की जनता को आशा बधी थी और वह बडी आशा जनता पार्टी की सरकार से लगाए बैठी थी लेकिन उस आशा के अन्दर निराशा का भाव पैदा हुआ है।

हमने घोषणा कर रखी है कि दस साल के अन्दर बेकारी और बेरोजगारी हम खत्म कर देंगे। लेकिन बजट को देखने से निराशा ही हाथ लगती है। इसमे बैर बराबरी को खत्म करने के लिए कोई प्रावधान नही किया गया है, किसानो को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके इसका कोई प्रावधान नही किया गया है, मूल्यो मे स्थिरता बनी रह सके इसका कोई प्रभावशाली उपाय नही किया गया है। किसान द्वारा पैदा की गई चीजो के मूल्यों की स्थिरता की कोई व्यवस्था नही की गई है। घाटे का बजट होने के कारण जो कारखानो मे चीजे बनती हैं उनके मूल्यो मे वृद्धि होगी। घाटे का बजट वहा अच्छा होता है जहा औद्योगिक मदी होती है और साथ ही जो औजार प्रधान होता है, जहा टैक्नोलौजी उन्नत होती है। भारत एक कृषि प्रधान विकासशील देश है और साथ ही मनुष्य प्रधान देश भी है। कृषि और मनुष्य प्रधान देश मे घाटे की अर्थ व्यवस्था कल्याणकारी नही हो सकती है। दुर्भाग्य से बीस पच्चीस वर्ष से जिस नीति पर सरकार चलती आ रही है उसको अब भी अपना लिया गया है और यह भी उसी का एक दुष्परिणाम है।

आप देखें कि किस प्रकार से गैर बराबरी को खत्म किया जा सकता है और साथ ही जो भारत मे आज फ्यूडल मैंटेलिटी है उस पर

रोक लगाई जा सकती है। अभी पूंजीवाद तो दूर भारत में सामन्ती व्यवस्था तक को खत्म नहीं किया गया है। सबसे पहले सामंती व्यवस्था को खत्म करना होता है उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की बारी आती है और उसके बाद ही समाजवाद आता है। फ्यूडल एलीमेंट्स को खत्म करने के बारे में आशा बंधी थी वह भी पूरी नहीं हुई है। आप कम से कम यह तो कहें कि एक व्यक्ति की, एक सरकारी अधिकारी की, कर्मचारी की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी तनख्वाह होनी चाहिये। मेरी राय में 2,000 रु० से ज्यादा मासिक किसी को नहीं देना चाहिये। एक वर्ष में 24,000 रु० होते हैं। आज एक व्यक्ति की औसत आय एक वर्ग की हिन्दुस्तान में 1,000 रु० साल है। आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 1 और 20 का अन्तर होना चाहिये। आज आप अगर ऐसा करते तो जनता पार्टी के ऊपर गरीब लोगों की आशा बढ़ती। इसलिये आप आय की सीमा बांधें और साथ साथ खर्चे की सीमा भी बांधे। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है आज खर्च पर रोक और उपभोग पर रोक। लेकिन जनता पार्टी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरा सुझाव है कि 24,000 रु० साल से ज्यादा जो खर्च करते हैं उन पर खर्च टैक्स लगाया जाय। उन पर 100 प्रतिशत टैक्स लगाया जाय ताकि सामन्ती प्रवृत्ति समाप्त हो सके। आज सारी सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। आय और खर्च की सीमा में कोई तालमेल नहीं है। एक व्यक्ति के पास 10 मकान रहें और एक के पास रहने के लिये एक हजार स्क्वायर फीट की जगह न रहे। इस उपभोग पर रोक होनी चाहिये। एक व्यक्ति के पास में मिल्कियत 10 लाख की हो सकती है लेकिन उसके पास में 10 या 20 जोड़े से ज्यादा कपड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिये उपभोग पर रोक होनी चाहिये। खर्च पर रोक सामन्ती पर रोक लगायेगी। और जिस तरह से दूसरे देशों ने तरक्की की है उस ओर इस बजट में कोई जिक्र नहीं है।

आज कृषि से जो आय होती है उस पर इन्कम टैक्स नहीं लगाया गया है। आज हिन्दुस्तान के बड़े बड़े पैसे वाले कृषि पर आय कर न होने के कारण क्या कर रहे हैं? वह मुश्किल से 100 क्विंटल अनाज पैदा करते हैं, लेकिन दिखाते हैं एक हजार क्विंटल और इस प्रकार ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं। जिस दिन यह घोषित कर दिया जायगा कि कृषि से और अन्य व्यापार से जो आय होती है उसको जोड़ कर इन्कम टैक्स लगेगा उस दिन वह खत्म हो जायगा। साथ ही यह लक्ष्य होना चाहिये जनता पार्टी का कि एक व्यक्ति और एक व्यवसाय। अगर यह लक्ष्य रखते हुए तात्कालिक रूप से यह घोषणा कर दी जाय कि वह व्यक्ति जिसकी आय 20,000 रु० किसी एक व्यवसाय से है उसको दूसरे व्यवसाय के अन्दर काम नहीं करने दिया जायगा तो उससे करोड़ों लोगों को देश के अन्दर रोजगार मिलेगा और सामन्ती मिटेगी, पूंजीशाही मिटेगी और गैर बराबरी खत्म होगी।

मान्यवर, कर वह अच्छे होते हैं जो सीधे होते हैं, मतलब सीधे लगते हैं। अप्रत्यक्ष करों की भरमार है। सब लोग आलोचना करते हैं। मैं वित्त मन्त्री जी को सुझाव देता हूं कि वह कर लगायें जो कि सौ में से एक या हजार में से एक के ऊपर हो सकता है। लगाये उस पर जिनके पास मोटर है। उस पर मोटर के उपभोग का कर लगाये। जिस प्रकार से रेडियो का लाइसेंस लेना पड़ता है उसी तरह से मोटर रखने वाले को 1,000 रु० उपभोग लाइसेंस का देना पड़ेगा। जो रेफ्रीजरेटर रखता है उसको 200 रु० उपभोग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी प्रकार गीजर, रेडियोग्राम, टेप रिकार्डर रखने वालों पर उपभोग कर लगाये। इन पर कर लगाये तो मुश्किल से एक हजार में से एक व्यक्ति को उपभोग लाइसेंस लेना पड़ेगा और सरकार को कम से कम 500, 600 करोड़ रु० की आय होगी। टी० वी० का लाइसेंस 50 रु० का है। क्यों नहीं 150 रु० करते हैं। टी० वी० कौन लोग रखते हैं? मुश्किल से एक हजार में

[श्री कल्याण जैन]

से 5 या 10 व्यक्ति रखते होंगे। लेकिन उनको नहीं छुआ गया है। इसलिये आप जनता पार्टी के दिये हुए वायदों को कि 10 साल से गरीबी और बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, इस प्रकार वह 50 साल में भी पूरा नहीं कर पायेंगे। इस पर आपको गम्भीरता से सोचना है।

अन्यथा, इसी तरह से स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को 35 करोड़ रु० पेंशन के रूप में दिया जाता है, उसी प्रकार भूतपूर्व संसद् सदस्यों को भी पेंशन दी जाती है। यह आपको बन्द करना चाहिये। इसी तरह से सेवा निवृत्ति की आयु 55 वर्ष रखी जाये और किसी को एक्स-टेंशन न दिया जाय। आज राजस्व के अन्दर जो वृद्धि हो रही है वह किस में हो रही है? आज सारा राजस्व जो खर्च हो रहा है वह पदों की पूर्ति करने के अन्दर खर्च हो रहा है। अर्थात् अनुत्पादक नौकरी करने वालों की संख्या बढ़ायी जा रही है। आज देश की ऐसी अर्थ व्यवस्था है कि किसी एक व्यक्ति को अनुत्पादक नौकरी में लगाने का मतलब होगा हिन्दुस्तान को पीछे ढकेलना। आज उत्पादन कामों में लोगों को लगाये। इस बात की चिन्ता न कीजिये कि उत्पादन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। इस बात का ध्यान रखिये कि उत्पादन कितने लोगों के द्वारा हुआ है। 5 प्रतिशत की जगह 3 प्रतिशत उत्पादन की वृद्धि हुई कोई बात नहीं है। हम को तो इस बात का ध्यान रखना है कि उत्पादन के अन्दर कितने लोगों को लगाया गया है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिये, बल्कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री चाहिये हिन्दुस्तान के अन्दर।

आज हिन्दुस्तान में छठी कक्षा से 3 भाषा का फार्मूला लागू किया गया है। मेरा निवेदन है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में 3 भाषा का फार्मूला नहीं है। कम से कम इसे छठी कक्षा के से बन्द करके आठवीं कक्षा से किया जाये। इससे हिन्दुस्तान के राज्यों में 100 करोड़ रुपये की बचत होगी और इससे अच्छे मास्टरों से अन्य अशिक्षित लोगों को शिक्षा दिलाई जा सकेगी। पब्लिक स्कूलों को भी समाप्त करने से करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है।

राज्यों के द्वारा भी भयंकर रूप से घाटे के बजट बनाये जा रहे हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा। बिहार की सरकार का घाटे का बजट 1 अरब 18 करोड़ रुपये का है। ऐसा शायद ही कहीं सुनने को मिला हो। तमाम प्रान्तों के घाटे के बजट हैं, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। मध्यम और अपर-मध्यम वर्ग के लोगों पर टैक्स लगाया जाये और छोटा पर खर्च किया जाये। अगर इस पर रोक नहीं लगेगी तो यह प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी और जनता पार्टी की सरकार और गैर जनता सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उद्योगों की सीमा बांध दें। कि कौनसा उद्योग कुटीर उद्योग और स्माल स्केल में आयेगा और कौनसा उद्योग बड़े उद्योग में आयेगा। आज बीडी कुटीर उद्योग में बनती है, उससे 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। जिस दिन बीडी स्माल स्केल में मशीन से बनने लगेगी, मुश्किल से लाख दो लाख व्यक्ति उससे रोजगार पा सकेंगे। इसलिये दियासलाई और बीडी के उद्योगों के बारे में घोषणा करनी चाहिये कि 4, 5 साल में इन्हें कुटीर उद्योगों में ला देंगे। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि दियासलाई का कारखाना जो कि विमको मल्टी नेशनल कम्पनी है, जहां मुश्किल से हजार, दो हजार आदमी काम करते हैं, उसको आग लगा देनी चाहिये। जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक लाखों लोग रोजगार नहीं पा सकेंगे। आज कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों की ओर ध्यान नहीं है।

आज आप सनलाइट, लाइफब्वाय, रेक्सोना साबुन की तुलना बाजार में कर सकते हैं। आपको इन पर एक्साइज बढ़ाना

चाहिये आज भी साबुन, तेल, मंजन और सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुएं बड़े उद्योगों के द्वारा, मल्टी नेशनल्स के द्वारा बनाई जाती हैं। इन पर एक्साइज शुल्क ज्यादा होना चाहिये। जो चीजें कुटीर उद्योगों स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के द्वारा बनाई जाती है, उन पर एक्साइज शुल्क माफ होना चाहिये तब ही वह कंपीटीशन में आ सकेंगे। जब मनलाइट एक रुपये में मिलेगा और हाथ से बना दूसरा 90 पैसे में मिलेगा तो सादा साबुन जनता नहीं लेगी, मनलाइट ही खरीदेगी। उसमें 1 और डेढ़ गुना का डिफरेंस होना चाहिये। साबुन में न किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है और न क्वालिटी की। इसलिये कुटीर उद्योग को प्रोटेक्शन देने के लिये जरूरी हो जायेगा कि हैवी इंडस्ट्रीज के अन्दर मल्टी नेशनल कम्पनीज द्वारा निर्मित वस्तुओं पर एक्साइज बढ़ावें।

आज वनस्पति घी बनाने वाले साबुन बनाते हैं। इनको क्यों न बंद किया जाये अगर साबुन को स्माल स्केल में कर देते हैं तो इससे लाखों लोगों को धन्धा मिलेगा।

शुगर, गन्ने, गुड़ की भी बहुत ज्यादा बात हुई है। आज जरूरत इस बात की है कि किसान को गन्ने की क्या कीमत मिलती है, इस बात की नहीं कि शुगर किस भाव पर मिलती है। जो शुगर बाजार में बिकती है उसके दामों में और कंट्रोल रेट की शुगर के दामों में सामजस्य किया जाये। मैंने सुझाव दिया था कि इससे 140 करोड़ बल्कि 180 करोड़ रुपये की एक्साइज में वृद्धि होगी, अगर आप एक्साइज 80 रुपये प्रति क्विंटल शुगर पर कर देते हैं। दोहरी मूल्य प्रणाली को खत्म कर दिया जाये। 180 करोड़ रुपया एक्साइज में ज्यादा मिलेगा और गुड़ 2 रुपये किलो मिलेगा और शुगर 3 रुपये के आसपास मिलेगी। हिन्दुस्तान के 8 करोड़ किसान जो खेती करते हैं, उससे उनको फायदा मिलेगा।

इसी प्रकार से कपड़ा उद्योग में भी निश्चित मात्रा में कंट्रोल का कपड़ा बनाने के लिये मजबूर किया जाता है, वह बन्द किया जाना चाहिये। कंट्रोल का कपड़ा किसी को भी सस्ते भाव पर नहीं मिलता है, वह कुछ सोसाइटी लेती है और ब्लैक में बेच देती है। श्री पटवारी ने ठीक ही कहा कि कन्ट्रोल और दोहरी मूल्य प्रणालियों को खत्म किया जाये। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि कंट्रोल क्लाथ को खत्म करें और साथ ही मिल प्राइस और उपभोक्ता प्राइस में 20, 25 प्रतिशत से ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये, आज यह 40, 45 प्रतिशत का अन्तर है।

इसी प्रकार से दवाईयों की बात बराबर इस सदन में कही गई है। दवाइयों में मल्टी-नेशनल कम्पनीज और बड़ी इण्डस्ट्रीज करोड़ों रुपया कमा रही हैं। जनता पार्टी की सरकार को बने एक साल हो गया है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे मुझे शंका होने लगी है कि कहीं वह लाबी तो काम नहीं कर रही है, जिस से मिनिस्टर और अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। आखिर हाथी कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित क्यों नहीं किया जाता है, ताकि दवाओं के पेटेन्टस के बजाये उन के कनटेन्टस बिकें। इसलिए यह जरूरी है कि हाथी कमेटी की सिफारिशों को तुरन्त कार्यान्वित किया जाये। श्री जनेश्वर मिश्र इस समय सदन में बैठे हुए हैं। मेरा आग्रह है कि वह इस ओर ध्यान दें।

मेरा सुझाव है कि वाहनों की खरीद के लिये सरकार और बैंकों के द्वारा कर्ज नहीं दिये जाने चाहिये।

जनता पार्टी की पार्लियामेंटरी पार्टी ने सभी संसद सदस्यों को एक परिपत्र भेज कर अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने के लिए कहा था। वास्तव में जनता पार्टी ने इस विषय में शुरुआत की है। हम ने अपनी सम्पत्ति का विवरण दे दिया है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उस का प्रकाशन नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि ऐसा नियम या कानून बनाया जाये

[श्री कल्याण जैन]

कि संसद सदस्य, विधायक, और यहां तक कि सरपंच, स्थानीय स्तर पर अपनी अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें, ताकि जनता को उस की जानकारी हो सके ।

जिस व्यक्ति की सम्पत्ति पांच लाख रुपये से ज्यादा है, उस का भी प्रकाशन होना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति दस हजार रुपये आयकर दे रहा है, उस की सम्पत्ति का भी प्रकाशन होना चाहिए ।

मेरा सुझाव है—इस सम्बन्ध में बनी एक कमेटी ने भी यही सुझाव दिया था—कि इस समय जो चौदह, पंद्रह बैंक हैं, उन्हें एमलगमेट कर के चार पांच बैंकों में परिवर्तित कर दिया जाये ।

एक व्यक्ति या एक कनसर्न का एक ही बैंक से सम्बन्ध होना चाहिए । आज एक एक व्यक्ति पांच छः बैंकों से सम्बंधित है, जिससे लाखों करोड़ों रुपयों की बदमाशी होती है ।

यह खुशी की बात है कि आज हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ रही है । इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे पास रिजर्व फ़ोरेन एक्सचेंज और अनाज का भारी स्टाक है । अगर हमारे पास रिजर्व फ़ोरेन एक्सचेंज और अनाज का स्टाक न होता, तो घाटे का बजट पेश करने पर 10 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हो जाती । लेकिन यह जरूरी है कि रिजर्व फ़ोरेन एक्सचेंज का सदुपयोग किया जाये । सीमेंट प्लांट, थर्मल प्लांट और पेपर प्लांट आदि का इमपोर्ट किया जाये, ताकि जिन चीजों की हमारे देश में कमी है, देश में उनका उत्पादन किया जा सके और इन उद्योगों में लोगों को काम भी मिल सके ।

कैपिटल गन्ज का लाभ केवल बड़े लोगों को मिला है, छोटे लोगों को नहीं । सोना, चांदी और मकान को छोड़ कर चल सम्पत्ति पर जो कैपिटल गेन दिया जा रहा है, उसे बन्द करना चाहिए । उस का दुरुपयोग हो रहा है। माननीय सदस्य, श्री सुबह मण्यम का यह सुझाव अच्छा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि अब तक कैपिटल गेन्स से किन लोगों को फ़ायदा हुआ है । पूंजी विनियोजन का फ़ायदा बड़े लोगों को ही मिला है । काले धन के बारे में माननीय सदस्य, श्री अमीन, ने सुझाव दिया है । यह घोषणा कर दी जाये कि जो लोग मकान बनाने, रेल की पटरी बिछाने और गंगा या कावेरी की सिंचाई योजनाओं पर रुपया लगायेंगे उन से यह नहीं पूछा जायेगा कि उन्होंने वह रुपया कहां से प्राप्त किया है । इस प्रकार दस हजार करोड़ रुपये को निर्माण और प्रगति के लिए काम में लाया जा सकता है । इस से लोगों को रोजगार भी मिलेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may kindly conclude now.

श्री कल्याण जैन: एक्साइज ड्यूटी को जो 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है, उसे खत्म किया जाये । पंद्रह लाख रुपये से ऊपर प्राडक्शन करने वालों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है । यह अच्छा नहीं है । इस तरह सरकार स्माल स्केल सेक्टर को फ़ायदा नहीं पहुंचायेगी और इस से करप्शन भी बढ़ेगा ।

अगर हिन्दुस्तान में कम्प्यूटर, हारवेस्टर और बड़े ट्रैक्टर का उपयोग होगा, तो हिन्दुस्तान में ग़रीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती जायेगी, और दूसरी तरफ़ अमीर लोगों की संख्या भी बढ़ती जायेगी । इससे मध्यम तथा निम्न-मध्यम वर्गों के बीच लड़ाई होगी, जैसाकि इस समय बिहार में हो रहा है । बड़े लोग तमाशा देख रहे हैं और बड़े लोगों के अखबार इस की खबरें छाप रहे हैं । हमारे देश में ग़रीब बोल नहीं सकता है, पढ़ लिख नहीं सकता है । उस में जान नहीं है । बड़े लोग मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास को आपस में लड़ाते रहेंगे । इसलिए

देश में कम्प्यूटर हारवेस्टर और बड़े ट्रैक्टर का उपयोग बन्द होना चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am calling the next speaker now.

श्री कल्याण जैन : स्वर्ण नियंत्रण कानून को वापस लेना चाहिए । कारों में डीजल इंजिनों का प्रयोग करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और पेट्रोल इंजिनों को ही बनाये रखना चाहिए । एस० टी० सी० और एम० एम० टी० सी० आदि कार्पोरेशन्ज का प्रजातंत्रीकरण होना चाहिए । हिन्दुस्तान के पब्लिक सैक्टर में करोड़ों रुपये लगे हुए हैं । इसलिए उन के प्रबन्ध को अच्छा बनाकर उनकी आय बढ़ानी चाहिए ताकि वह पैसा देश के निर्माण में लग सके ।

न्यायालयों के बारे में श्री शान्ति भूषण ने कहा है, जो अखबारों में आया है कि किसी भी केस का छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट तक एक साल में फैसला हो जाना चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Kalyan Jain please take your seat now. I now call Mr. Balakrishniah.

श्री कल्याण जैन : मुझे आशा है कि वित्त मंत्री मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे ।

SHRI T. BALAKRISHNIAH (Tirupathi): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the present budget is an *ad hoc* budget. There is no rational thinking in it, nor is any special philosophy involved in the budget. It is said that the budget is disappointing and it has failed to solve the economic problems of the country in general and the problems of the economically backward areas in particular. Just like there are backward people, similarly, there are backward areas also in the country and this budget does not seem to worry about the backward areas in the country. I am referring particularly to the Rayalaseema area of Andhra Pradesh, which is very much backward economically as it is a rain-fed area. The normal rainfall in Rayalaseema is far below the average; rather it is scanty and so there is very little of agriculture and industries. The result is that a large number of people, both educated and uneducated, are unemployed because there is no scope for employment for them. Even though that area is full of natural and mineral resources, Government have not taken any initiative to exploit them. Even when some industries are sponsored, they are started mostly in urban areas like Hyderabad, Bangalore or Jubbalpore. If this is the attitude of the Government, how can they solve the problem of unemployment or improve the condition in the rural areas of the country? The rural areas can be improved only when there is decentralisation of industries. More industries should be set up in rural areas than in urban areas.

This budget has been criticised even by the industrialists. They are afraid that even though the production may increase, there will be no purchasing power in the hands of the people. Government have not taken the initiative to create purchasing power among the people. Further, the massive increase in the rate of general excise duty from 2 to 5 per cent on unspecified items, coupled with the uncovered deficit in the budget, may lead to a general increase in prices and may accentuate the inflationary pressure.

I would say that one of the reasons for the increase in prices is the check-posts. Dal, which costs Rs. 250 per quintal in Rajasthan, by the time it reaches Madras or some other place costs Rs. 550 per quintal, because the traders have to pay so many unauthorised payments to so many people at the check-posts. So, the traders are forced to pass on this burden to the poor consumers by increasing the prices. That is why even when the wholesale price is low, the consumer price is very much higher. The result is that the common man is suffering. What steps have the Government taken to check this type of unauthorised price rise

[Shri T. Balakrishniah]

with regard to essential commodities like wheat, rice, sugar, oil and dal, which are articles of daily use?

Here I would like to read a quotation of a Roman philosopher, who was a great economist. I am tempted to quote it because this is an unbalanced budget. He says:

> "The budget should be balanced; the treasury should be replenished, public debt should be reduced, the arrogance of officialdom should be tempered and controlled and the assistance of foreign loans should be reduced, lest the State becomes bankrupt; the people should be forced to work and not to depend upon Government for sustenance."

What steps have been taken to see that the people are given work? How are they going to provide work to the people? If people have work, there will be no starvation As long as there is no work, there will be unemployment and there will be starvation and there will be agitation and both educated and uneducated youths will join the agitation.

AN HON. MEMBER: In that quotation there is a suggestion that the people should be forced to work

SHRI T. BALAKRISHNIAH: Yes, that is true. If you create opportunities for them to get employment, they will work If you do not create opportunities, there will be no work for them.

The overall deficit in the Budget of 1977-78 has gone up to Rs. 975 crores and it may go upto 1050 crores. What I submit is that there are a number of expenses which the Ministry has to cut down. Very recently, I read in the newspapers that the Ministers who have been pleading all these days that they have come from humble middle class families, that they will improve the economic conditions of the people and will look after the welfare of the people, are now asking for more amenities and lakhs of rupees have been spent for providing additional amenities for them. Crores of rupees are being spent on foreign tours. During the election time, all these Janata Ministers have been going by helicopters, spending a lot of money. This is unnecessary expenditure which costs much to the State Exchequer. This unnecessary expenditure must be stopped. Delhi Airport is already a first-class airport They are going to spend another Rs. 4 crores in order to improve it further. They are spending crores of rupees in order to beautify all the cosmopolitan cities. When there are villages in the country where even after 30 years of Independence there is no drinking water, no roads, no schools and health facilities, why should they spend money to beautify the cities of this country? This is what I call a wasteful expenditure and this expenditure is responsible for this deficit.

The Department has no programme by which they can tap the rich people in order to get more money. The deficit is record breaking in the history of Indian Budgets. The rich people are spending money lavishly on their luxurious living.

The other day, our Prime Minister said in Coimbatore that Minority Commission would be appointed. I read in the newspapers that a minorities Commission had already been appointed He said that it would be appointed If this is the Minorities Commission, is it to abolish the reservations given to backward and other minorities? Or will this Government continue the reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes after 1980? My fear is that they may stop giving reservations to SC&STs after 1980 in view of the appointment of these commissions and all that.

The atrocities on Harijans have been increasing particularly after the advent of the Janata Party rule at the Centre. Some rich people in the rural areas are under the impression

that the Government at the Centre is ruled by the rural rich persons. This wrong impression has to be erased. The Prime Minister while speaking in Coimbatore said that atrocities committed on Harijans were more in the days when Congress was in power than at present. The Home Minister, Mr. Charan Singh, while replying to the discussion on the Report of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the last session also gave the same statement. Mr. Karpuri Thakur, Chief Minister of Bihar, who has failed to maintain law and order in his State, during his election tour in Andhra Pradesh also uttered the same words. I want to know whether all these people are comparing the number of atrocities committed on Harijans during these 30 years to that of the number of atrocities committed during these 11 months as a defence for these people or they are going to take effective steps to put an end to these atrocities. There should be an end to these atrocities. The Janata Government committed to special opportunities for backward classes and the reservation from 25 per cent to 36 per cent for those classes in Government jobs.

Now there is a demonstration, a counter demonstration in certain classes, in certain States. What steps they are going to take to see that these reservations are given for the backward classes and other minorities in this country.

There is a wide discussion on Centre State relationships and much has appeared in the press. Many States are pressing for more powers. There is a suggestion for revival of the Zonal Council. The Zonal Council would provide a forum for meeting the representatives of the States as well as Centre at a periodical interval for a disussion on common problems. A great deal has to be done to bring about closer cooperation between the two. One is not merely referring to irrigation and power plants, but more important are industrial and fiscal measures for removing vexatious imbalances in wealth tax rates and others. The Zonal Council could be a useful instrument for promoting this kind of Centre-State cooperation. They have failed to live upto the expectations because the States would not take it seriously enough. The Council needs to be activised to meet and discuss wider range of issues.

Sir, I conclude by saying that people will ultimately measure the performance of both Centre and State Governments only by one yardstick and that is whether or not the policies they have followed, the plans they have drawn and the schemes they have implemented are going to better their living conditions, living conditions of the common people in the country. I want that this should be kept in mind by the Janata Government and they should try to improve the conditions of the common people in this country.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Ram Vilas Paswan.

श्री डी० जी० गवई (बुलडाना) उपसभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था की बात नही है।

श्री डी० जी० गवई **

MR DEPUTY-SPEAKER: You expunge the whole thing.

श्री डी० जी० गवई वाक आऊट करते है और सदन से उठ जाते है।

Shri D. G. Gavai along with Shri Kacharulal Hemraj Jain then left the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You expunge the whole thing. It is very

**Expunged as ordered by the Chair.

[Mr. Deputy-Speaker]

unfortunate that the Member should have made such a statement There has been no partiality Every group is being given time here In spite of it, if some Members or some small group want precedence over bigger groups, I cannot help it

Yes, Mr Paswan

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कुछ नीति का मामला सरकार के सामने रखना चाहता हू। पहला नीति का मामला यह है कि

MR. DEPUTY-SPEAKER I must make one thing very clear that those individuals or Independent Members who might have spoken on the Railway Budget and also Motion of Thanks, want to speak again on this they will not be permitted now

श्री राम विलास पासवान पहली चीज यह है कि भारत की जनता अपनी गरीबी से इतनी त्रस्त नही है जितना कि दूसरो की अमीरी से त्रस्त है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मत्री जी यहां बैठे हुए है। मैं उनसे एक ही आग्रह करूगा कि जनता पार्टी की सरकार बनने के एक साल के बाद वे कम से कम इस सदन म यह घोषणा कर दें कि हम एक-दस का रेशो नही, एक-बीस का रेशो नहीं, एक-सौ का रेशो इस देश मे रखेंगे। आज टाटा और बिरला की आमदनी एक तरफ है और दूसरी तरफ़ गरीब की प्रतिदिन की आमदनी है। इसलिए मैं वित्त मत्री जी से आग्रह करूगा कि वे कम से कम एक और सौ का अन्तर रख दें। अगर यह भी सभव न हो तो एक और हजार का अन्तर रख दें। लेकिन एक तरफ तो एक व्यक्ति की प्रतिदिन की आमदनी साढे तीन लाख रुपया और एक गरीब की आमदनी प्रतिदिन तीन और डेढ रुपया है। मैं समझता हू कि यह लाख और दो लाख का प्रतिदिन का अन्तर है।

सरकार ने एक भूतलिंगम कमेटी बनाई थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस समिति की रिपोर्ट कब तक सदन के सामने आयेगी? कब उनकी रिपोर्ट पर आप अमल करेंगे? हम लोगो को यह चीज अभी तक मालूम नही हो सकी है।

आज दाम बाधने की बात कही जाती है। बहुत से माननीय सदस्यो ने इस चीज को यहा पर उठाया है। लेकिन यह बात तो दूर रही आपने कर किन चीजो पर लगाये है? जो जीवनोपयोगी वस्तुए है उन पर लगाये है। कोयले बिजली, गैस कैरोसीन आयल सबकी कीमते बढने जा रही हैं। देहात मे लोगो के खाना बनाने का एक मात्र साधन कोयला है और वही लोगो को महगा मिलेगा। एक साधन गरीबो के लिए बिजली और वही महगी हो जायेगी। शहर के लोगो के लिए गैस है, कैरोसीन आयल और उन सब की कीमतें बढ जायेंगी। क्या आप यह कह सकते है कि यह सब काम आप गरीबो के लिए कर रहे है? जब किसान द्वारा पैदा की गई चीज का दाम बढता है तो बहुत हल्ला होता है। लेकिन आज आप गन्ने के दाम को देखें और चीनी के दाम को देखे। मैंने सदन मे प्रश्न उठाया था और मत्री जी से प्रार्थना की थी कि जनता पार्टी की सरकार बनने के एक साल के बाद आप जितनी भी जीवनोपयोगी वस्तुए है उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन मालूम करके हमे दे दें और साथ ही साथ गन्ने आदि खेती की जो चीजे है उनका उत्पादन का खर्च क्या पडता है इसका हिसाब लगा कर दे दें, चीनी के उत्पादन का कितना खर्च पडता है, एक दवाई जो टेरामाइसीन है या कोई और जीवनोपयोगी वस्तु है उन सब–वस्तुओ की कास्ट आफ प्रोडक्शन आप हमे बता दें तो माननीय सदस्य खुद मालूम कर लेंगे कि बडे बडे उद्योग धधे चलाने वाले जो लोग है, जो कैपिटलिस्ट लोग है वे कितना मुनाफा कमा रहे हैं और किसान को कितना मुनाफा या घाटा हो रहा है। तब आपके

अफसरों से हिसाब लगवाने की जरूरत नहीं रह जायेगी। मैं चाहता हूं कि यह जानकारी हमें आप एकत्र करके दे दें।

आपने कहा है कि चालीस परसेंट आप ग्रामीण विकास के लिये खर्च करने जा रहे हैं। कहां यह चालीस परसेंट बनता है। 20, 22 या 23 परसेंट ही आपने इस काम के लिए रखा है जो गांवों के एक्चुअल विकास में लगेगा। इस बात को मैं मानता हूं कि विगत सरकार द्वारा जितना खर्च किया जाता था उससे यह अधिक है। लेकिन जिस नारे को दे कर हम जीत कर आये हैं, जो बातें हम गांव वालों को कह कर आये हैं उनकी इससे पूर्ति नहीं होती है। आज तक हम उनको यही कहते रहे हैं कि आप हमारे बजट को देखना। लेकिन इससे निराशा हुई है।

हमारे साथी ने कहा है कि एक हजार करोड़ का घाटा इसमें दिखाया गया है। क्यों नहीं आप इस घाटे की पूर्ति बड़े बड़े पूंजीपतियों पर, टाटा, बिड़ला आदि जो बड़े बड़े परिवार हैं उनसे करते हैं। यह चीज हाउस में आ जानी चाहिये और तब पता चल जायेगा कि कौन इसका विरोध करता है और कौन समर्थन करता है। एक बार घाटे को आप पूरा करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाएं तो सारी चीज साफ हो जायेगी। इसके लिए आपको निश्चित रूप से अपना मन बनाना होगा, कोई न कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना होगा। अमीर भी खुश, गरीब भी खुश, मध्यम श्रेणी भी खुश और अफसर और चपड़ासी भी खुश इस तरह से सरकार नहीं चलेगी। स्पष्ट नीति आपकी होनी चाहिये। किसके लिए हम सब काम कर रहे हैं यह स्पष्ट हो जाना चाहिये।

भाषा नीति को आप लें। धारिया साहब बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी इस बात को वह शिक्षा मंत्री तक अवश्य पहुंचा दें। हम लोग जीवन भर रटते रहे हैं, जो कोई भी डा० लोहिया का चेला या शिष्य रहा है, वह रटता रहा है, हमेशा से नारा लगाता रहा है कि राष्ट्रपति का बेटा या चपड़ासी की हो संतान, बामन या भंगी का बेटा, सब को शिक्षा एक समान। हमेशा कहते रहे हैं कि शिक्षा एक समान होनी चाहिये। कुछ राज्यों की सरकारों ने इसको लागू कर दिया है। बिहार की सरकार ने लागू कर दिया है। गंगोत्री जहां से गंगा का पानी निकलता है यहां हम कहते हैं कि पब्लिक स्कूलों को रहने देंगे, अंग्रेजी को रहने देंगे। डर के मारे कब तक आप भागेंगे? मैं भाषा विवाद में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैंने और मेरे साथियों ने हजार बार कहा कि दो भाषायें कम्पलसरी कर दी जाये, एक दक्षिण की और एक उत्तर की भाषा। दोनों को कम्पलसरी करके एक धारा बहाई जाये। उसमें हमको घाटा नहीं है। जो दक्षिण के साथी हैं उनको स्वयं घाटा है। दक्षिण में एक से एक बढ़ कर लोग पैदा हुए हैं, एक से एक बढ़ कर इंटेलेक्चुअल लोग पैदा हुए हैं। समाज सेवी पैदा हुए लेकिन वह पूरे देश के नेता नहीं बन पाये भाषा की वजह से क्योंकि उनकी भाषा सीमित क्षेत्र में रह जाती है। इसलिये देश में सच्ची गंगा बहनी चाहिये, इसके लिये आवश्यक है कि दो भाषाओं को कम्पलसरी कीजिये—एक उत्तर की भाषा और एक भाषा दक्षिण की। और अंग्रेजी को दफ़ना दीजिये, उसके मोह में न पड़िये। आप हिन्दी को अपना दुश्मन न समझें और हम आपकी भाषा को अपना दुश्मन न समझें।

बेरोजगारी के बारे में सरकार ने घोषणा की है कि 10 साल में बेरोजगारी हटायेंगे, गरीबी हटायेंगे। एक साल पूरा हो गया क्या जितने बेरोजगार थे उसमें से 10वें हिस्से को आप रोजगार दे सके? नहीं दे पाये। जो आपका बजट है उसके तहत आप 10 साल तो क्या 100 साल में भी बेरोजगारी को नहीं हटा सकते हैं। यह सरकार के बलबूते के बाहर की चीज है। क्या आपने कभी

[श्री राम विलास पासवान]

सोचा कि जितना रुपया खर्च होता है लडको की पढ़ाई पर 26 साल के बाद 27 साल मे वह बूढ़े हो गये। उसके बाद उसको नौकरी नही मिलती है। तो या तो आप नौजवान को रोजगार दें, नही तो बेरोजगारी का भत्ता दें। यह सरकार का दायित्व हो जाता है। इसी प्रकार हमारा कहना है कि आयु की सीमा को आप खत्म कर दीजिये। जब हमको 55 या 58 वर्ष की आयु तक नौकरी करने का अधिकार है तो हम 54 वर्ष या 57 वर्ष तक नौकरी पा सकते हैं, भले ही हम एक साल नौकरी करे। आप क्यो रोक लगाते हैं। हम 26 साल के बाद बूढे हो जायेगे और आप 70 साल तक जवान रहे। तो या तो 27 साल के पहले सब को नौकरी दीजिये, नही तो 57 वर्ष तक नौकरी पाने का हमको अधिकार होना चाहिये। आप आयु की सीमा को समाप्त कीजिये।

जाति नीति के बारे मे हमने शुरू से कहा है, आज बिहार की स्थिति को जो रूप दिया जा रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार मे दुखद स्थिति हो गई है। इसी को रोकने के लिये हमने शुरू मे नारा लगाया था पिछडा पावे सौ मे साठ। और उसमें हमने हरिजन, आदिवासी और तमाम औरत समाज को रखा था। उसमें कही कोई कटुता की बात नही थी। ऊची जाति की भी जितनी औरतें थीं उन सबको हमने पिछडी श्रेणी में रखा था। यह डा० लोहिया की दृष्टि थी। और यह लोग जानते थे कि आने वाली पीढ़ी को आप नहीं रोक सकते है, उसको कभी भी बरगलाया जा सकता है। इसलिए जाति नीति का मामला स्पष्ट रूप से देश के सामने रखना चाहिए और विचार कर के एक स्पष्ट नीति तय करनी चाहिए।

बहुत खेद होता है कि हरिजन का सवाल उठता है। मैं बजट को देख रहा था कि आपने हरिजनों के लिए कितना रुपया रखा है, पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये कितना रखा है। 1 प्रतिशत। आज भी जब कि दिन रात हरिजन, आदिवासी की दुहाई देते हैं लेकिन बजट मे उनके लिए रखते हैं 1 प्रतिशत। हमारे कांग्रेस के लोग जब इधर से मामला उठता है तो बहुत खुश होते हैं। मैं पूछना चाहता हू कि आप 9 मार्च के अखबार को देखें। कर्नाटक मे आपकी सरकार है, और वहा पर हरिजनो को कुएं पर चढ़ने नही दिया जाता है। घोषणा की जाती है कि यह कुआ है जहा हरिजन नही जा सकता है। और जब हरिजन जाता है पानी भरने के लिए तो पुलिस के सामने उसको कोड़े से पीटा जाता है और पुलिस अफसर वहा चुपचाप खडा देखता है। हमने काल अटेंशन दिया है, पता नही स्वीकार होगा कि नही, लेकिन मैं कहता हू कि आप हमें ही क्यो कहते है? जहा आपका राज्य है वहा भी तो देखिए कि उनके साथ आपकी सरकार क्या व्यवहार कर रही है।

जो अफसरशाही है इसके लिए सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। मैं तो जब भी टेलीफोन करता हू सेक्रेटेरियट मे तो सुन कर दग रह जाता हू कि 75 प्रतिशत लोग हिन्दी नहीं जानते हैं। मुझे कहना पडता है कि आप हिन्दी जानते है कि नही ? तो जवाब आता है कि नही मैं हिन्दी नहीं जानता। और हम लोग कहते है कि हिन्दी मे भी काम करो, और अंग्रेजी मे भी काम करो। यहां आई० ए० एस० अफसरों का एक गिरोह बना हुआ है। हम लोग जब किसी चीज के विषय मे मंत्री महोदय को लिखकर देते हैं तो जवाब आता है कि मैंने स्वयं इसका निरीक्षण किया, मैंने स्वयं कागजात देखे और यह तथ्य पाया है। मैं कहता हूं कि शायद ही कोई मंत्री ऐसे होंगे जो एम० पी० के लिखे पत्र को और जो अफसर ने जवाब बनाया है, उसको पढ़ते होगे। सिर्फ वह दस्तखत ही करते हैं। जो जवाब अफसर बनाकर देते हैं वह हम लोगो के पास आ जाता है।

वह बड़े बड़े अफसर, आई०ए०एस० अफसर होते हैं, उनसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं

होता। आई०ए०एस० के विरुद्ध कौन इन्क्वायरी करे? इनका एक गिरोह बना हुआ है और उसमे ऐसा है कि अगर किसी आई० ए० एस० अफसर के विरुद्ध इन्क्वायरी हो तो उसके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट नही देनी है।

आज सरकार के फैल्योर का मामला हो रहा है। सरकार का फैल्योर नही होगा, इन्होंने कौन से अफसर को हटाया है? जितने भी एमर्जेंसी के समय अफसर थे वह आज वही पर बैठे हुए है।

यहा इस समय आवास मत्री श्री सिकन्दर बख्त नही है और श्री राम किंकर भी नही है। 18 मई को यहा की विकास मीनार मे मेरा भाषण हुआ था। 19 मई को वहा एक कमल कान्त चड्ढा नाम के जूनियर स्टैनोग्राफर, जा कि अप्रैल मे सीनियर स्टैनोग्राफर हो गया था, ने 18 मई का एक महीने की छुट्टी ली, चूकि उसे रिलीव नही किया गया था, इसलिए उसने छुट्टी ली। वह कहने के लिए गया कि हमको रिलीव किया जाए, लेकिन उसको रिलीव नही किया गया। 19 मई को सवेरे वह गया और उसने फिर कहा कि हमको रिलीव कीजिए, नही तो मेरे 5 बच्चे भूखे मर जायेंगे, बाप मेरा अकेला है। लेकिन उसको कहा कि मर जाओ। वह बेचारा 17 मजिल की विकास मीनार से कूदकर मर गया, उसने 19 मई को आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसी दिन हमको टेलीफोन आया, श्री सिकन्दर बख्त घर पर थे, मैंने उनको लिया और वहां पर गया। वहा के सेक्रेटरी ने कहा कि यह अफसर इदिरा गाधी और सजय गाधी का भेजा हुआ एक पी० एल० मदान है जो कि एडीशनल एडवाइजर था, जो ओवरएज हो चुका था, लेकिन फिर भी उसको पैसा कमाने के लिए रखा हुआ था। लोगो ने वहा कहा कि पी०एल० मदान की वजह से ही इसकी हत्या हुई है। उसके पास से एक चिट भी निकली जिसमें लिखा हुआ था कि इसी अफसर के कारण उसको आत्महत्या करनी पड रही है। वह चिट भी श्री० एस०पी०-म पुलिस अधिकारी को दिया गया।

मिनिस्टर ने घोषणा की कि प्रधान मंत्री फड से 5 हजार रुपए उसके परिवार के लिए दिए जाते हैं। मिनिस्टर ने कहा कि कहा है पी० एल० मदान, उसको पकड़ो और जेल के बन्द करो। मालूम हुआ कि पी० एल० मदान लिफ्ट से निकलकर चला गया है। तीन दिन के बाद जब अखबार मे देखने को मिला तो पुलिस रिपोर्ट मे यह कहा था कि पी० एल० मदान उस दिन छुट्टी पर थे।

आप समझ सकते है कि जहा भारत सरकार का मत्री जाता है, एम०पी० जाता है, बिहार के मुख्य मत्री श्री कार्पूरी ठाकुर वहा गए और सारे आफिसर्स और एम्पलाइज ने कहा कि उसी के कारण आत्महत्या की, वह रूम मे कही बैठा हुआ होगा, और तीन दिन के बाद जब मामला आता है तो मालूम हुआ कि वह अफसर तो उस दिन आया ही नही था। यह अफसरशाही का नगा नाच है। इसलिए इस अफसरशाही के चलते, मैं यह आपसे कहता हू कि हरिजनो और छोटे वर्ग के लोगो का भला होने वाला नही है।

आज बेलछी काड पर आप लोग सस रहे है, लेकिन आप भूल रहे है कि आपके शासन काल मे बिहार मे रूपसपुर मे कितना वभित्स काड हुआ था? 200 आदिवासियो के घरो को जिन्दा जला दिया गया था और बाद मे रिपोर्ट आई कि 14 लोग मरे है। एक कांग्रेस के नेता थे उस समय जो कि बिहार के स्पीकर रह चुके है, उन्होने और उनके भाई ने अपने हाथो से जलाया था। उसके बाद मामले को दबा दिया गया। एमरजेंसी के दौरान क्या हुआ?

आज हमको इस बात की खुशी है कि भारत सरकार की इतनी उदारता तो जरूर है कि कम-से-कम थोडी सी भी कही घटना होती है, तो पार्लियामेंट मे उसकी गूज होती

[श्री राम विलास पासवान]

है और हम उसको रख लेते हैं, हमको खुशी है कि आप भी उसमे साथ देते हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि आपके यहां भी यदि कोई | घटना घटे,| तो उसकी चर्चा होनी चाहिए । मैं तीन दिन से देख रहा था कि हमारे कर्नाटक के कोई साथी नही जो पार्लियामेंट में हरिजनो का सवाल उठायें, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लायें, लेकिन आप नहीं ला सके हैं। आप अभी भी अपनी सरकार को देखते हैं और बोलते नही कि कहीं इन्दिरा गांधी हम पर नाराज न हो जाये। अगर हम कहीं बोले तो हमारी सरकार के विरुद्ध पड जायेगा।

आज कही भी हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों पर अगर अत्याचार होता है, जुल्म होता है तो उसको इस सदन में उठाते हैं और दिलेरी के साथ अपनी बात कहते हैं। लेकिन आप लोग इस तरफ ध्यान नही देते है।

हमें एक बात और बहुत अफसोस के साथ कहनी पडती है। हम लोग जिस गुरु के चेले है, आप दिल्ली शहर मे कहीं भी चले जाइए, मैं नही कह सकता हूं कि क्या लैंगुएज मैं इस्तेमाल करू, प्राय और सब लोगों का कही न कही स्टेचू लगा हुआ है, लेकिन डा० राम मनोहर लोहिया और डा० श्यामा-प्रसाद मुखर्जी, श्री सुभाष चन्द्र बोस, डा० अम्बेडकर जैसे आदमियो का जिनका देश मे व्यापक स्थान है, उनका स्टेचू कही नहीं है। खास तौर पर डा० राम मनोहर लोहिया और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो बिकुल ही नही है।

जब सार्वजनिक छुट्टी का मामला आता है तो जनता पार्टी की सरकार को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करनी चाहिए कि इन माननीय नेताओं के जन्म दिवस को यह मानती थी।

मैंने जो मामला उठाया है, वह नीति का मामला है—जाति नीति, भाषा नीति, शिक्षा नीति, विदेश नीति, सेना नीति, दाम बांधो नीति। अगर हम इन नीतियो का अनुसरण करेंगे, तो हमे सफलता मिल सकती है। लेकिन जो हमारा स्तम्भ है, अगर हमने उसे छोड दिया, तो लाख बजट बनाने से भी कुछ नही होगा। इस बजट की प्रतिया एक ट्रक मे लद कर पार्लियामेंट हाउस में आती है। लेकिन हम लोगो के एक साधारण से कार्यकर्ता से जाकर पूछिये—सारा बजट उसको रटा हुआ है। सरकार इस आधार पर काम करे, इसमे मुल्क की भलाई है, हमारी और आपकी भलाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे अवसर दिया।

SHRI R KOLANTHAIVELU (Tiruchengode) Respected Deputy-Speaker, Sir in welcoming this budget, let me say that this first budget of 1978-79, to me it appears, is an excellent budget after the Janata Party's Government coming to power But, inherently, this is an unhealthy one because the Finance Minister s speech and the budget for 1978-79, of course, have its merits and demerits also But, I do not say anything about the unnecessary remarks

15 53 hrs

[SHRI M SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

Here, our Finance Minister has miserably failed to consider the matter of Ganga-Cauvery Scheme. At least he ought to have uttered a word about it but he has not. If you want to eradicate the food problem, water problem etc Ganga-Cauveri scheme must be taken into consideration.

The Finance Minister's budget speech had no doubt caused many eyebrows to be raised. He has no doubt stated that if poverty and unemployment are to be eliminated, the agriculture, small industries and rural industries must play an important role. Of course, I welcome this suggestion. If it is so, the first step would be to eradicate the problem of scarcity of food. If the Ganga-Cauvery Scheme is taken up, the unemployment problem will be done away with and the whole soil of our country will be made into a green field. Now only the northern part of our country has sufficient water for its storage, but the southern part has not. The budget is very much silent about the fast improvement of agricultural production and the allocation of fund is very low. This could have been much more, then only we can say that it is somehow better than the previous Government in this particular aspect.

The budget had a serious impact on the progress and future of the industries especially on the engineering side. After the budget, to-day, the engineering industry has to face a grave situation because of taking away some of the clauses such as 'incentives'. In the budget, the imported machinery had been made cheaper by reduction of duty and the Indian product had been made more costly because of enhancement of the excise duty on the unspecified products from 2 per cent to 5 per cent. The increase is also due to the cost of power and coal. The curbs on publicity and advertisement expenses and the discontinuance of export market development allowance, that permitted deduction of the amount of expenditure, it would have a big impact on the promotion of engineering exports.

As stated above, the harsh impact of power levy created serious problems for many States and industries because their selling price of aluminium has already been raised; the producers of caustic soda and other chemicals are also likely to raise their prices. The price of fertilisers and cement that are the common-man's needs, of course, will have to be raised due to the levy on electricity.

Though several incentives were offered by Janata Government soon after it came to power to induce and encourage the private sector to participate in the rural development, yet nothing of that sort is encouraged upto the expectation of the common-man in the budget.

More than that the poor record of collection of income tax and corporation tax during the current year which has fallen below the budget estimate instead of progressive growth, the cause of it has not been explained in the budget.

The sale of gold at the international price is a main feature of the economy of our country and this has to be observed very seriously.

Though the Janata Government has taken very serious steps with regard to the price situation of our country—inspite of conflicting views in the higher level—the prices were not brought under control. We can very well see that the whole-sale price index is coming down but the retail and consumer prices are shooting up simultaneously. Why is this happening? This is happening because the Ministers are dancing to the tune of big traders. It becomes clear from the Budget that the Finance Minister has aimed to take away the financial powers of the States so that the States may approach the Centre for more aid and thus the Centre is able to exercise its influence. On the other hand the Finance Minister should have attempted to improve the purchasing power of the individual or a family which he has failed to do so through this budget. He tries to ride two horses at a time, where in this respect one cannot.

[Shri R. Kolanthaivelu]

Sir, as a Member from Tamil Nadu and on behalf of my party, namely, All India Anna-DMK I want to lodge protest on the Floor of this House about the miseries and sufferings experienced by the people I also would like to lodge protest against the levy on electricity.

I would conclude by saying that the Janata Government has miserably failed to redress the grievances of the poor classes. When a common man goes to purchase something, he cannot get the things as he desires even though he spends a lot of money to purchase it This should be improved We have mainly to take into consideration the difficulties of the poor class people.

Further, Sir, if you want to eradicate the poverty and food problem in our country, then you have to pay sufficient attention to the Ganga-Cauvery scheme in the budget Sir, the Cauvery River runs in my constituency also, but I know how much difficulty there was because of non-availability of water In Tamil Nadu some parts are well irrigated whereas in some parts there is non-availability of water Water problem should be given serious consideration in the budget, then only the food problem will get solved In the rural areas also, there is a positive demand from every society including the labour class for uninterrupted drinking water supply There is a perennial water difficulty faced by the rural masses in most parts of the country Though our country is not financially sound to take up huge schemes in every sector, the Government's primary function is to see that every individual, particularly in the rural areas, is assured of perennial drinking water supply Of course, the Janata Government is faced with a lot of problems It is just like a new born baby but it has to grow steadily and it should become a healthy child Then only our country will prosper Sir, with these words, I conclude

16 hrs.

श्री राममूर्ति (बरेली) : सभापति महोदय, 1978-79 का जो बजट पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समाज के जो भिन्न भिन्न अंग हैं, मैं देख रहा हूं, सभी में इस बजट का आह्वान भी किया गया है और वित्त मंत्री जी की प्रशंसा भी की गई है। प्रशंसा इसलिए की गई है कि लोगों को जब किसी चीज से आराम मिलता है तो वे उसकी चर्चा करते हैं। आज बावजूद इतना डेफीसिट फाइनेंसिंग होने से, करीब 800-900 करोड की डेफिसिट फाइनेंसिंग हुई उसके बाद भी कीमतें रुकी ही नहीं हैं बल्कि गिरने लग गई है। इससे हर घर में बड़ा इत्मीनान और संतोष होने लगा है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस बजट में जो प्रायरीटीज फिक्स की गई है उनसे लोगों को संतोष हुआ है और हालात सुधरने की आशा बधने लगी है। बजट में इस बात की कोशिश की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 85-90 प्रतिशत आदमी जो गरीबी और अज्ञानता की हालत में डूबे हुए थे उनको ऊपर उठाया जाए। बैकवर्ड, हरिजन, आदिवासी, पढ़े-लिखे और बेपढ़े-लिखे सभी लोगों के लिए इस बात की कोशिश की गई है कि उनको ऊपर उठाया जाए और उनकी गरीबी को दूर किया जाए। जिन लोगों पर आज तक कभी ध्यान नहीं दिया गया था उन पर ध्यान दिया गया है, बजट में उनके लिए निर्देशन दिया गया है। इस से भी लोगों में खुशी हुई है।

सभापति महोदय, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहें कि इस बजट में सारी बातें अच्छी हैं। हमारे जो अपोजीशन के लोग हैं वे इस बजट में कोई भी अच्छी चीज देख ही नहीं पाते हैं। जैसे किसी को कैटरेक्ट हो जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता कुछ वैसी ही कैफियत उनकी भी हो गई है। मैं करीब करीब 32 साल से लेजिस्लेचर में बैठता आया हूं मैंने कभी ऐसा नहीं पाया कि बजट पेश किया गया हो तो सारे हाउस में उसकी तारीफ की गई हो।

जो मुखालिफ लोग हैं वे अच्छाइयों के बावजूद बुराई ही करते हैं। कुछ ऐसी आदत और परम्परा सी बन गई है और उसी परम्परा को हमारे अपोजीशन के जो लोग हैं, निभा रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो यह कहे कि तीस साल के कांग्रेस के राज में कोई भी अच्छाई की बात नहीं हुई। देश में इण्डस्ट्रीज लगी, तिजारत बढ़ी, खेती अच्छी हुई और उसके साथ-साथ अस्पताल खुले, नहरें बनाई गईं, स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटीज खुलीं, चार हजार करोड़ का फारेन एक्सचेंज का रिजर्व बना लेकिन इसके साथ-साथ इस मुल्क में 65 फीसदी लोग पावर्टी लाइन से नीचे चले गए। गरीबी ही नहीं, दरिद्रता की हालत में आ गए। 109 यूनिवर्सिटीज खोली गईं लेकिन एम० ए० पास लड़के 100 रुपए की नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जो बेपढ़े-लिखे लोग हैं जैसे कारपेंटर, मैसन, वायरमैन या मजदूर—उनसे आप तिरछी नजर से कुछ कह दीजिए तो वे उसी वक्त छोड़ कर चले जाते हैं। उनमें एक तरह की करेज आ गई है लेकिन बेचारे पढ़े-लिखे लोगों में करेज भी नहीं है—इस तरह की तालीम है। ऐसा राज रहा, ऐसी तालीम रही। इस बजट में कोशिश की जा रही है कि सभी को पहले एलीमेंटरी एजूकेशन मिले। जिसकी जानकारी भी दी गई है। कोई भी बच्चा बिना पढ़ा-लिखा नहीं होना चाहिए। जो लोग 40–50 साल की उम्र के हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत तालीम होनी चाहिए। इस बात की तरफ उस सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। उसी की वजह से आज देश में भारी अज्ञानता है, गरीबी है। यह तीस साल का राज हुआ। जहां इसकी कुछ अच्छाइयां थीं उन्हीं के साथ ये बुराइयां भी उस राज की रही हैं जिससे हमारा मुल्क दरिद्र बन गया है। इस बजट में इस बात का जिक्र किया गया है कि हम गरीबी और बेकारी की जो बड़ी भारी समस्या है उससे लोगों को बाहर निकाल कर लायेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, अज्ञानता को दूर करेंगे।

जब 1950 में हमारा संविधान बना तो उसके अन्दर कुछ निर्देशन सिद्धांत रखे गए थे जिनका भी पिछली सरकार ने पालन नहीं किया। उन निर्देशन सिद्धांतों के सम्बन्ध में मैं सिर्फ एक दो बातों का ही जिक्र करना चाहता हूं। संविधान में पहला डायरेक्टिव यह था कि केन्द्र और राज्यों में ऐसी नीति को चलाया जाएगा जिससे समानाधिकार लोगों को प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिन्दगी की सुविधायें मिलें। दूसरा डायरेक्टिव यह था कि जो हमारी मौलिक वस्तुएं हैं, रोजाना की जरूरत की वस्तुयें हैं, हमारे साधन हैं, उन साधनों के ऊपर समाज का कन्ट्रोल होगा। उन साधनों के जरिए से ज्यादा से ज्यादा आदमियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। ग्रेटेस्ट गुड आफ दि ग्रेटेस्ट नम्बर। लेकिन इस तरफ भी उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात यह है कि समाज की जो सम्पत्ति है, वह थोड़े से लोगों के हाथों में सीमित हो कर न रह जाए जिससे समूह को क्षति पहुंचे। सभापति महोदय, आप देखेंगे कि जो नीति अपनाई गई, उसी की वजह से तीसरे प्लान से लेकर बाद वाले प्लानों तक हजारों करोड़ रुपया समाज के अन्दर इन्वेस्ट किया गया। उसका फायदा मुश्किल से दस फीसदी लोगों को ही मिला। 90 फीसदी आदमी उससे वंचित रह गए। जो डाक्टर्स हैं, वकील हैं, कान्ट्रेक्टर्स हैं, बड़े बिजनस वाले हैं, मिडिल क्लास वाले हैं। दुकानदार लोग हैं, उन्हीं की तरक्की हुई बाकी गरीब लोग और गरीब होते गए। 85 फीसदी आदमी देहातों में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। उनके अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं, जमीन पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, खेती का माडर्न सिस्टम उन तक पहुंच नहीं पा रहा है जिससे कि उनकी पैदावार बढ़ती। इसी कारण से गरीब और गरीब होते गए। जिनके पास तिजारत है, कारखाने हैं, स्माल इंडस्ट्रीज हैं, जो पैसा बचा सकते हैं, वे अपने पैसे को रिएम्प्लाए करते चले गए और धनी हो रहे हैं।

[श्री राममूर्ति]

दो-तीन साल पहले फ्रन्टियर गांधी बादशाह खां यहां आए थे। उन्होंने कहा कि मैं हिन्दुस्तान का स्वराज्य दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद और बैंगलौर में देख रहा हूं लेकिन हिन्दुस्तान के जो बाकी देहाती क्षेत्र हैं उनमें वैसी ही झोंपड़िया हैं, वैसी ही सड़कें है। गरीब आदमी वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। उन आदमियों के पैरों में जूते नहीं हैं, उनकी खेती बाड़ी पुराने किस्म की है। ये विचार उस आदमी के थे जिसने इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया था। उसे यह सब देख कर दर्द हुआ। यह हालत हिन्दुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने पैदा कर दी है।

बजट कोई खर्च और आमदनी का बेलेंसशीट ही नहीं होता है। यह एक डायनेमिक इस्ट्रूमेंट है। इसके जरिए से गवर्नमेंट की पालिसी का पता लगता है। यह उसकी पालिसी का मिरर है। किस तरह से गवर्नमेंट इसके जरिए प्रगति की ओर देश को ले जाना चाहती है, कितनी तेजी से प्रगति करना चाहती है। इससे यह भी पता लगता है कि हमारे समाज का जो विकास हो रहा है वह सही ढंग से, सन्तुलित ढंग से हो रहा है या नहीं। यह देखने की जरूरत है। इस माने में यह बजट सराहनीय है। वित्त मंत्री की लोग इसीलिए प्रशंसा और तारीफ कर रहे हैं।

बजट में बड़ी भारी रकम ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी और बहबूदी के लिए रखी गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि रुपया दे देने से ही काम नहीं चलेगा, हमारे यहां वह इनका स्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम काटेज इंडस्ट्री को सठावा दे सकें। किस तरह से उसको मुल्क में आगे आप बढ़ा सकते हैं इसको आप देखें। पांच लाख स्माल स्केल इंडस्ट्रीज इकाइया देश में हैं। करीब 55 लाख लोगों को रोजी भी देती हैं। 39 परसेंट प्रोडक्शन भी देश का वहां होता है। लेकिन इन में से साढ़े चार लाख इंडस्ट्रीज शहरों में हैं और रूरल एरियाज में कुल पचास हजार हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया तो किसी ब्लाक में काटेज इंडस्ट्री को लगा देने से कोई लाभ नहीं होगा। शक्कर जैसी चीज के कारखाने जब मुल्क में लगने लगे तो उस वक्त इसको भी प्रोटेक्शन दिया गया था क्योंकि बाहर की शक्कर सस्ती होती थी। जिस तरह से तब सरकार ने शक्कर के कारखानों को प्रोटेक्शन दिया था उसी तरह से घरेलू धन्धों के लिए भी आपको इनफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और इस कार्य में आपको ब्यौरेवार जाना पड़ेगा। कौन सी व्यवस्था इसके बारे में हो इसको आपको देखना पड़ेगा। कमीशन में प्लानिंग के काम को जो देखते हैं उन्होंने मुझे बताया है कि कोई इनफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं बना है। जो मौजूदा ब्लाक डिवेलेपमेंट के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं वे इस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वर्कशाप खोलने पड़ेंगे। बजट सैशन के खत्म होते ही सैमिनार करने पड़ेंगे। खाली सरकारी नौकरों से काम नहीं होगा। जो पब्लिक वर्कर हैं उनको भी एसोसिएट करना होगा आनरेरियम दे कर। पता लगाना होगा किसी जगह जो चीज पैदा होती हैं वहां उस पर आधारित कौन सी काटेज इंडस्ट्री बन सकती है, मजदूर कहां मिलेंगे बाजार किस तरह से मिलेगा, प्रोटेक्शन किस प्रकार दी जाएगी। टाटा का सोप चल रहा है। हम लोग उसके मुकाबले में सोप निकाल कर चल सकें, यह मुमकिन नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में बना सोप उस सोप का मुकाबला नहीं कर सकता है। सरकार ही उसका मुकाबला कर सकती है। इस माने में जो सबसे बड़ी जरूरत है वह इस बात की है कि ऐसा इनफ्रास्ट्रक्चर बने ताकि काटेज इंडस्ट्री आसानी से स्थापित हो सके और चल सके। इसमें थोड़ा समय भी लग जाए तब भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। रोजगार अगर हम चाहें कि एक दिन में मिल जाए तो वह नहीं मिल सकता है। कंडिशन एक दिन में खराब नहीं होती हैं। 25–30 साल का बैकलाग है जो जनता सरकार के सिर पर आया है। एक दिन में कंडिशन बिगड़ती भी नहीं है और सम्भलती

भी नहीं है। जब मशीनरी तैयार हो जाएगी, लोगों के इरादे बन जायेंगे तो काम आसान हो जाएगा। रोजी तब एक एक साल में दस दस और बीस बीस और तीस तीस लाख लोगों को मिलने लगेगी।

आप अमरीका और रूस की बात करते हैं। उनकी बीस बाईस करोड़ की आबादी है। वहां बच्चे ज्यादा पैदा करने पर इनाम दिया जाता है। हमारी साठ करोड़ की आबादी है। तीन गुना है। अमरीका की भूमि हम से तीन गुना है, रशिया की आठ गुना है, आस्ट्रेलिया की तीन गुना ज्यादा है और आबादी सात करोड़ है। उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं।

यहां जिक्र हुआ है कि एक कारखाना अभी लगा है, हमारे देश में जिस पर 23 करोड़ लागत आई है और उसमें आठ आदमियों से ही काम होता है। कम्प्यूटरों की मदद से इलैक्ट्रानिक्स के जरिये सारा काम चलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के कारखानों की भारत को जरूरत है? क्या इनको आप रोकेंगे नहीं? इस तरह की योजनायें हमारी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती हैं, उसकी आकांक्षा की तर्जुमानी नहीं कर सकती है। सरकार को कदम कदम पर ध्यान देना होगा कि नीतियों का सम्पादन ठीक हो रहा है।

देश की हालत क्या हो गई है? अशोक होटल में चार सौ रुपया रोज कमरे का देना पड़ता है, इसमें रोटी, खाना पीना कुछ शामिल नहीं है। क्या सरकार इस तरह की चीजों को रोकेगी नहीं? एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ ओबराय शैरेटन में चाय पीने के लिये चला गया। दो प्याले चाय ली और सोलह रुपये का बिल आ गया। यह बातें मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। यह हालात हवा का रुख बताते है। मुल्क किधर जा रहा है इससे इसका पता चलता है। दौलत कोई कारखानेदार अकेले पैदा नहीं करता है। हजारों लोग मिल कर खून पसीना बहाते हैं तब पैदा होती है। आपको देखना होगा कि उस दौलत का बटवारा भी ठीक हो रहा है या नहीं। इस तरह की जो चीजें हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें। अगर इस पौलिसी का परिपालन ठीक नहीं हुआ और सुपरवीजन ठीक नहीं हुआ इसके माने यह हैं कि जितनी भी हमारी अच्छी बातें हैं वह लाउड थिंकिंग बन कर रह जायेंगी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं सब के के लिये और सरकार के लिये भी, कि आपकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं रहना चाहिये। एक साल पहले गांधीजी की समाधी पर हम सब लोग राजघाट गये थे और शपथ ली थी कि सरकार के तरीके, हमारे रहन सहन और अपने अखराजात ऐसे रखेंगे जो कोई ऊंगली न उठाये। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन हम सब उसके लिये जिम्मेदार हैं। हम इकोनामी की बात तो करते हैं पर सही माने में अगर देखा जाये इकोनामी तब तक नही हो सकती है जब तक हमारा दृष्टिकोण न बदले। सरकारी कर्मचारियों का जीवन का एक तरीका बन गया है। कंजरवेटिव लोग हैं उस दायरे से नही निकल सकते हैं। वह तभी निकल सकते है जब हर विभाग मे एक कमेटी हो जिसमें सरकारी अफसर हों, और जनता के प्रतिनिधि भी हों और वह एक एक आइटम को देखें कि कहां फिजूल खर्ची है। इत्तफ़ाक की बात है मैं पिथौरागढ़ गया वहां नेहरू सेन्टर है सोचा कि कुछ अच्छा काम होता होगा। पता लगा कि वहां फुटबाल होता है, कैरम वगैरह होता है। और जब उनका फर्नीचर देखा तो दंग रह गया। सारा टीक का फ़र्नीचर, कालीन और गलीचे बिछे हुए थे। इकोनामी इस तरह से हो सकती है? गांव में रूरल बैंक खुला और सारा फर्नीचर उसका लखनऊ से गया, जबकि बरेली में खुद लकड़ी का ही बड़ा काम होता है। हजारों फैमिली यहीं लकड़ी का काम करती हैं। लेकिन फ़र्नीचर लखनऊ से गया। तो जिस

[श्री राममूर्ति]

मन्त्री जी को इन बातों का नोटिस लेना चाहिये और उनके जरिये से जो नौकरशाही है उसके दिमाग के अन्दर भी इस विचार को बैठाना है । मैं यह नहीं कहता कि नौकरशाही को देश से प्रेम नहीं है, पर एक लाइफ का तरीका बन गया है जिससे वह हट नहीं पाते हैं । और यह बात कोई नाराजगी के साथ नहीं बल्कि सद्भावना के साथ करनी चाहिये कि कहां खर्च कम कर सकते हैं । इस तरह से करोड़ों रु० बच सकते हैं जिससे मुल्क को काफ़ी लाभ पहुंचाया जा सकता है ।

एक बात और है, यद्यपि उसका जिक्र कम हुआ है, लेकिन मैं करना चाहता हूं । यह बड़ी खुशी की बात है कि आज जो हमारे पड़ौसी देश हैं उन सबसे हमारे अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं । आपसी टेंशन कम हो रही है, फौजों का खर्चा भी कम हो जायेगा । और इसके लिये हमें सराहना करनी चाहिये अपने विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी जी की और उसके ऊपर अपने प्रधान मन्त्री की जिन्होंने इस एटामिक और न्यूक्लीयर सवालों पर जो कि अमरीका की तरफ़ से उठे, प्रधान मन्त्री जी ने एक मज़बूत कदम उठाया और इंकार किया इस तरह की बातों में पड़ने से, और कहा कि आगे चल कर भविष्य में भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे संसार में न्यूक्लीयर स्टाक पाइल्स को खत्म कर देना चाहिये । ऐसी नीति प्रशंसनीय है ।

दो, तीन छोटी छोटी बातें और कहना चाहता हूं सोना बेचने के बारे में जिक्र किया गया है । सरकार अपने खजाने में से 500 करोड़ का गोल्ड बेचेगी और उसके जेवरात बना कर बाहर के मुल्कों को भेजे जायेंगे । कोई ज्यादा गोल्ड हमारे यहां नहीं है, वह तो अमरीका, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस और इटली में है । लेकिन इस तिजारत को किया जाये क्योंकि मिडिल ईस्ट और यूरोपियन मुल्कों में भारतीय जेवरात की बहुत मांग है । इटली में 2, 3 साल के अन्दर मिडिल ईस्ट कन्ट्रीज़ के अन्दर 1,000 करोड़ रु० के जेवर बेचे । तो हमें भी इंटरनेशनल प्राइस पर गोल्ड खरीदना चाहिये, क्योंकि हमारे यहां 10 ग्राम सोने के दाम हैं और जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है उसमें 233 रु० का फ़र्क है, सरकार रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन्स के जरिये से जेवरात बनवा सकती है और इन कन्ट्रीज़ को बेच कर जहां जेवरात की काफ़ी मांग है, हजारों करोड़ रु० सरकार पैदा कर सकती है जिससे हम अपने डैफ़िसिट की भी पूर्ति कर सकते हैं । इतना बड़ा फील्ड और इतना बड़ा स्कोप इस मुनाफे के लिये है । हमें उससे फायदा उठाना चाहिये ।

हमारी एजूकेशन का मामला बड़ा अहम है । हमारे साथी ने जो कुछ कहा है, मैं उनके समर्थन के लिये यह बात कह रहा हूं कि हम बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क से अंग्रेजी हटने न पावे । जब तक यह प्रवृत्ति बनी रहेगी, इस मुल्क के लोगों और सरकारी अधिकारियों के बीच खासा हाइट्स बना रहेगा । जिस प्रकार से अंग्रेज़ समाज के लोगों को दूर रहने देता था, पास नहीं आने देता था कि छूत न लग जाये, वही स्प्रिट आज भी बनी हुई है । बड़े अधिकारी रिप्रैजैन्टेटिव्स को अपने पास बैठाना पसन्द नहीं करते हैं । जो सैरेमोनियल्स हुआ करते हैं, उनमें गैर सरकारी लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता है यह वहां देखा जा सकता है । इससे लोगों में नाराजगी की फीलिंग पैदा हुआ करती है, सद्भावना पैदा नहीं हुआ करती । हम एक देश के रहने वालों में जब अन्तर नहीं है तो फिर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये । हमारे मन में ऐसी फीलिंग नहीं आने देना चाहिये कि सरकारी अधिकारियों और हमारे बीच में अन्तर है । उनको यह महसूस करना चाहिये कि गरीब लोगों को, और कमजोर लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाये । वह अफसर सिर्फ दफतर में बैठ कर 200, 400 फाइल

निबटा लेते हैं लेकिन आज फील्ड वर्क की भी ज्यादा जरूरत है ।

आज रैवेन्यु, पुलिस और ला एण्ड आर्डर का काम किस तरह से बिगड़ा हुआ है, लेकिन किसी अफसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने दफ्तर में इसे देखने की फुरसत ही नहीं है । मेरा कहना यह है तालीम की तरफ जरूर विशेष ध्यान दिया जाये । जब तक शिक्षा पद्धति बदली नहीं जायेगी, तब तक इस देश में जो उत्थान हम करना चाहते हैं जिससे गरीबी, बेकारी, अज्ञानता और बीमारी दूर हो, कार्य पूरा ही नहीं पायेगा । आज बेकार की तालीम दी जा रही है । एक एक आदमी 4, 4 सब-जैक्ट्स में एम० ए० पास कर लेता है लेकिन जानता कुछ नहीं है । उसकी यूटिलिटी नहीं है । अंग्रेजों के लिये तो यह ठीक था क्योंकि उनको क्लर्कस की जरूरत थी, लेकिन हमें क्लर्कस की जरूरत नहीं है । हमें तो उन लोगों की जरूरत है जिनकी देश की रचना में दिलचस्पी हो, जो यहां की आर्थिक नीतियों को समझ सकें और उसके अनुसार कार्यवाही कर सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Mr. Chairman, Sir, I take this opportunity to congratulate the Government for having sanctioned the Upper Indravati project at a cost of Rs. 220 crores. It is going to benefit the Kalahandi constituency. It will generate 600 megawatts of hydro-power and irrigate 5 lakh acres of chronically drought-affected and backward area of this country. Had this been taken up in 1969, it would have cost Rs. 89 crores. Now, it is going to cost Rs. 220 crores. It is a good thing that the Prime Minister is visiting my constituency on the 9th April and inaugurating this project. On behalf of the people, I express my sincere gratitude to him. It is a good thing that it has found a place in the 6th five-year plan.

In this regard, I beg to submit that it should be completed according to the time-schedule. It has to be completed within a period of 9 years. It should be completed in time. Otherwise, the estimate is likely to escalate and it will completely upset the planning.

This budget is conspicuous in the absence of any suggestion to remove the regional imbalances. In spite of 25 years of planning, there has been no impact in certain regions in this country. A study will reveal that the regional disparities have been aggravated. As the saying goes, the strength of the chain lies in the weakest link. A study of the past performance makes a very sad commentary.

A study of the State *per capita* income which constitutes a dependable composite indication of relative prosperity or backwardness of different States, shows that Orissa is one of the States having a very low *per capita* income. The gap between national *per capita* income and State *per capita* income, which was Rsfl 80 in 1950-51, increased to Rs. 96.3 in 1974-75 and Rs. 87.3 in 1975-76. In 1976-77 the *per capita* income in Orissa is likely to decline on account of unfavourable weather conditions prevailing in the State. ,

If you make a study of the Plan-outlays State-wise, you will be surprised to find that the allocation is always more for affluent States. For an affluent State like Punjab the *per capita* outlay in the First Plan was Rs. 175 while for Orissa it was only Rs. 56. Similarly, in the Second Plan it was Rs. 146 for Punjab and Rs. 54 for Orissa. In the Third Plan, it was Rs. 212 for Punjab and Rs. 120 for Orissa. During the Fourth Plan period, Punjab was split into Punjab and Haryana. The Plan *per capita* allocation during the Fourth Plan was

[Shri P. K. Deo]

Punjab Rs. 316, Haryana Rs. 358 and Orissa Rs 113. In the Fifth Plan the same story has been repeated—Punjab Rs. 748, Haryana Rs. 599 and Orissa Rs. 267, and an affluent State like Maharashtra Rs. 460. Increased outlay for more affluent States simply widens the gulf of disparity between the advanced and backward States. I am stressing this point now because the Sixth Plan is on the anvil. I would request that there should be no repetition of the old mistake. In fact, this is one of the promises in the Janata Party Manifesto I hope there will be no inconsistency between precept and practice.

Even within the State there are regions within are much more undeveloped. Even though those areas are rich in natural resources, they have remained untapped and so those areas remained backward always. That is the reason why during the discussion on the President's Address, my friend, Dr. Basant Narayan Singh pleaded for a separate State of Chottanagpur. Like Chottanagpur and Eastern U.P. Western Orissa is also comparatively much more backward. In spite of the natural resources, the standard of living of the people of that area is much below the poverty line.

That is why the previous Government taking expert advice from Messrs. Kuljeans and M. N. Dastur; suggested the establishment of the second steel plant at Nayagarh in Keonjhar district. But I am surprised to hear that it is going to be shifted to the Minister's constituency at Paradip. It should not be done. Similarly, for the aluminium plant the more suitable place is Jaipatna in Kalahandi district, so that the electricity from the Indravati power house in Kalahandi can be used for this plant, because for an aluminium plant electricity is the raw material and it should be cheaply available. Since we would be generating 600 kw of hydel power, this is the ideal place. Further, 15 miles away, from that place, in Bafalimali, we have mineral resources, about 196 million tonnes of established high grade boxite ore, according to the Geological Survey of India. Yet, instead of putting up an aluminium plant there, now it has been suggested that it should be shifted to Koraput.

Similarly, there is the Rangali dam project which will submerge large areas of alluvial tracts and displace 80,000 people. Now there is a talk that a project will be taken up at Tikarpara, at the cost of the people of West Orissa. I would, suggest that this project should be considered on humanitarian consideration. If the Government want all round development of Orissa, every part of Orissa should be simultaneously developed, not one part at the cost of the underprivileged people of another part where the people are below the starvation line. So, I strongly oppose this Rangoli project and proposal for Tikarpara project.

Coming to the hard realities of Budget, I would be failing in my duty if I do not speak unpalatable truth. This Budget is highly inflationary Rs. 1050 crores deficit is unprecedented and unthinkable. Experts say that the prices will shoot up by 11 per cent. But I believe that the prices will shoot up by 15 per cent. The purchasing power of the rupee will also go down. I was listening with rapt attention to the speech of my friend. Prof. R. K. Amin. He was expecting a moon that the balance of trade may improve, that there may be remittances from the Gulf countries and we will be able to make up the deficit. But, I think, he is in the midst of a mid summer night dream.

Further imposition of excise duty will lead to industrial recession. The prices of every consumer item will go up and all those items will be

available in plenty in the shops but there will be no purchasing power of the people to buy them. The Finance Minister has cast his net of indirect taxation on every conceivable item. In this regard, I beg to submit that since these duties fall on either crucial production inputs or almost on all commodities, there is bound to be upward push to the prices of most manufactured products. It is well known that excise duties impinge more harshly on small scale units *vis-a-vis* large scale units. Since in industry large scale production is generally cheaper than small scale production, the ability of the large scale firms to hear the burden of additional duties is greater than that of small scale firms.

Then the entire economic thinking behind the Budget does not appear to be in favour of promotion of lower capital intensification.

Sir, while this country has been passing through power crisis and non-availability of power and as a result of that so many working days of the industry are being lost, I am surprised to find that the Finance Minister comes with the proposal to put a duty of Rs. 5/- per ton on coal and two paise per unit on electricity generated. Power is the most important means of production. Even for raising coal, we need electrical gadgets and for using those electrical gadgets, we will be needing power. So, we are creating a more vicious circle. So far as electricity is concerned, it is in the Concurrent List and I find that various State Governments also have put duty on electricity. So, I would like to be assured that there should be no double duty on electricity generated or consumed from the Central side and from the State side.

My next feeling is that it will stagnate industrial development. Though the purpose is to lay emphasis on rural industries and it seems to me a very noble objective, I do not think it would be so easy to achieve it. What is rural industry? How can a rural industry be started with an amount of Rs. 10,000 on which the concession given is only 50 per cent? Even this concession is being given for the new equity shares of new companies. I can hardly understand how they will be able to get any dividend because gestation period would not have passed by that time. So, in this respect, I beg to submit that if the intention is rapid industrial growth, incentives should be given for larger investments in the new corporate sectors.

An attempt has been made in this regard. Although it is a laudable attempt, it is not an adequate attempt. Last year, some concession was given on capital gains and it has been withdrawn before the objective could be achieved.

Another big problem is how to utilize the black money. By demonotization of one thousand rupee note, no problem has been solved. Only the tip of the iceberg has been touched. There is plenty of black money in this country. We have seen how money flows in the elections. Even in the post-election period, there is horse trading of the MLAs. How this mony is being utilized? The other day, in reply to a question, the Government gave a list of nearly 200 companies who subscribed more than Rs. 1 lakh to the souvenirs of the various political parties. If the Government wants that this black money could be utilised for nation building purposes, they can take a leaf from Belgium. In the post-war period, in Belgium, they gave full authority to all those possessing money to go in for tenements, and nobody was going to ask them from which source they got the money and the entire Belgium was rebuilt within a short time, even though Belgium was totally destroyed in the Second World War.

If you want to put an end to the effect of black money, I beg to submit that all the political parties should

[Shri P. K. Deo]

be registered under the Registration of Society Act of 1860, and they should submit their annual audited accounts for public scrutiny. Then only you can stop this black money.

I would like to draw your attention to another constitutional issue and that is Article 269 of the Constitution. In Article 269 of the Constitution, it has been very clearly stated that any collection from advertisements or newspapers should be fully assigned to the States. But, I think, there has been a deliberate infringement of the Constitution by taking away the fiscal power, from the States and Centre is arrogating that power. I think some thought should be given to this aspect.

There has been no indication of curbing wasteful expenditure, administrative waste specially on Defence In the context of our present better relations with our neighbours, we can reduce our Defence expenditure. The administrative machinery should tighten their belt and public sector undertakings should ensure better capacity utilization They should compete with the private sector. I cannot understand why any price preference or purchase preference should be given. The prices should be decided according to the normal law of supply and demand and consumer is after all the king; he has to pay every pie through his nose All permits and quota system should go away and the creative initiative of the man should be utilized fully so that we can march on the road to progress. If any preference has to be given, it should be given to small scale sector. In this respect, I would submit only one instance. In so far as PCC railway sleepers are concerned if the small scale industry can produce concrete sleepers according to ISI standard and if they can stand vigorous test, then the preference should be given to them instead of asking the mohopoly houses or public sector undertakings to start manufacturing these sleepers.

I take my hat off and give my congratulations to the Finance Minister for the outlay of Rs. 500 crores for the dairy development in the country—Operation Flood. He comes from the Kaira district which famous milk project "AMUL," we all know. I sincerey hope that all the districts will be converted like Kaira six years from 197-777.

Lastly I conclude with the remark that while the public debt has increased from 16,000 crores of rupees in 1973-74 to Rs. 29,000 crores in 1978-79, an increase of nearly 70 per cent in 5 years while the increase in national income is only 20 per cent. So this aspect has to be borne in mind.

On the whole, without raising the purchasing power of the rural people this Budget will drain the rural purchasing power and their saving capacity.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): The budget of any government is a key document which briefly ruminates on the past, surveys the present and affords us a peep into the future, the prospects of progress and achievment in the future. As such the general disclussion on the Budget is an important event in Parliament and, therefore, I had thought and expected that it would be allotted more time than had been done. I have got before me figures for the last few years from 1970 and I have found that in all these years the time allotted or utilized has been from 18 to 20 hours. Even in the moribund Lok Sabha of the emergency in 1976, the time actually spent and utilised was 17 hours, and last year, the first year of the Janata government, the time spent was 20 hours 26 minutes. I hope the time will be increased so that more members can participated..... (*Interruptions*).

SOME HON. MEMBERS: Time must be increased.

AN HON. MEMBER: The Minister can reply on Monday.

MR CHAIRMAN You can represent it to your Whip

SHRI HARI VISHNU KAMATH Last year it was 20 hours 26 minutes

Yesterday my hon friend on the opposite side Shri T A Pai waxed loud and eloquent and said—these were his very words—that politics in this country had a vested interest in poverty No Member of the Congress Party could have made a more candid confession I think it will rank as the most candid confession of the year, if not of the decade, by the Congress because that was the slogan, *Garibi Hatao*, which swept him, his leader whom he followed meekly and timidly for six years and then exposed her and repudiated her before the Shah Commission very recently, to power He and his Party and his leader came to power 1971, exploiting powerv *Garibi Hatao*, a hollow and hypocitical slogan with which they bamboozled the gullible people in our country Actually, the result was *Garibon Ko Mitao* and not *Garibi Hatao* during six years from 1971—77

Here I have some tell-tale figures as to what they did what the Congress Party did since 1952 The second Five Year Plan stated that the number of unemployed was 55 lakhs in 1955 The Third Five Year Plan said that in 1961 the number of unemployed had increased to 90 lakhs At the end of the Third Plan, in 1966 the unemployed numbered 150 lakhs After three years of the Plan holiday 1966—69 the number increased to about 200 lakhs or 2 crores By the end of 1976 the total number of those unemployed stood at 3 5 crores approximately Unemployment in India is about 8 per cent It is possibly the highest proportion all over the world Under-employment is endemic and wide-spread

The growth of population has contributed only marginally to this phenomenon Population has grown 1-1/2 times durtig the last 25 years but unemployment has grown seven times between 1952 and 1976 The then Government's policy of large scale industrialisation resulted in a situation that in 30 years only 55 lakhs jobs were found in the large industrial sector Emphasis was laid on large industrial sector and the urbanisation of India by Pandit Jawahar Lal Nehru but towards the end of 1963, during the mid term apraisal of the then Plan he confessed (I was then a Member of the House) that the Plans had gone awry, had gone haywire, because over-ephasis had been laid on gigantism, giantism—I am not sure what word he used,—and more attention should have been paid to small industries, cottage industries, village industries and small irrigation tanks and to agriculture But that was too late He passed away a few months later—in 1964

In the 1961 census the proportion of agricultural workers among all the cultivators was 16 9 per cent In 1971 census it grew upto 25.4 per cent By 1976 it had increased further and now it stands at 30 per cent approximately In physical terms it means that about 2 crores, 20 million petty cultivators have been reduced to the status of landless workers during 1961 to 1976, in fifteen years time

Concentration of our resources on big industries and urbanisation had resulted in the stultification of our countryside, and consequently no new dynamism has been generated which could absorb the unemployed

I am glad that the Finance Minister has tried to make a frontal attack on this basic malaise of our country —poverty and unemployment This was the note on which he ended his speech on the 28th of February I quote the last sentence

"The economic situation of the country is exceptionally favourable

[Shri Hari Vishnu Kamath]

at present for a bold step forward. This Budget is such a step." This is the gilded hope. But there is a leaden anxiety—contract between the gold and lead—and the Minister has stated perhaps outside the House. I am not sure where, that much depends upon the implementation, efficient implementation, of the projects by State Administration, by the State Governments. He has tried to pump in funds naturally because the policy of the Janata Government in conformity with the policy of the Janata Party, more allocations have been made for the rural sector, for the countryside. for developing the rural people and the countryside. But, here again the kingpin or the linchpin of the entire operation is land reforms

What is needed is expeditious and efficient implementation of land reforms, so that the landless cultivators, the landless labourers, will be given some little homestead of their own. some little huts of their own, some wherewithal to cultivate their lands. Collectiveism may not suit us, but we should encourage the service cooperatives and I think—if I may make that suggestion—the Government should make out a definite plan to see that cooperatives of agricultural workers are given all facilities for starting cottage industries and for the cultivation of reclaimed waste lands.

Coming to the same sector of rural industries, cottage industries, village industries and so on, I must say, due emphasis must be laid on these. which will generate employment. Why? Because, this is what has been calculated by an economist regarding the assessment of the employment potential involved in large-scale industry, small-scale industry and the cottage industry.

Sir, it has been calculated that in respect of the Large-scale industry, for the purpose of creating one job, the scale of investment required is of the order of Rs. 30,000.

Sir, in respect of the Small-scale industry, for the purpose of securing one job, the investment would be of the order of Rs. 30,000.

Now, in respect of the cottage industry, for securing the same job, the investment needed is only Rs. 2,000.

Therefore, Sir, in our country, where capital is so scarce. cottage industries can give employment to fifteen times more number of persons for the same investment as in a large-scale industry. This is my point. In conformity with our Economic Policy Statements, Government should declare these cottage industries as priority sectors for bank finance Rural industries in each district should be helped by banks in respect of their raw materials and so on. Basic village industries should be established there with financial assistance from the commercial banks and other financial institutions. The Reserve Bank of India and other commercial banks should immediately be directed to help these village industries in every way. Each of our Nationalised Banks should be asked to specialise in one particular industry.

Sir, the least that the Government can do, is to prepare a list of luxury goods and services, and they should declare that no Bank Credit shall be made available hereafter to the production of those luxury goods and services.

I will come to another cognate question, Sir. and that is, Agricultural Income-tax. I am of the view personally, that there should be an Agricultural Income-tax. You may introduce Agricultural Income-tax with a celling a limit, of income of, say, Rs. 15,000 or Rs. 20,000. At present ordinary income-tax limit is Rs. 10,000, I think.

AN. HON. MEMBER: It is a State subject.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: But we can give a lead or advise to the States from here. We can do that. Make it Rs. 20,000 in respect of the Agricultural Income-tax and that will take care of the question of the Sales-tax.

16.54 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair.*]

I say this because, as you know, there is a certain allergy to the abolition of Sales-tax by the State Government. If the Agricultural Income-tax is introduced, this problem could be solved.

Sir, I would like the Government to give thought to this question of imposing agricultural income-tax.

Now, coming to the land reforms question, the Congress Government, for thirty years, had only mouthed the slogan of landreforms but they had not undertaken any serious effort to introduce expeditiously and efficiently the landreforms which they had talked much about It is hightime for the Janata Government to take it up soon and see to it that it is efficiently enforced, because, without that, all this money is not likely to benefit and reach the poor peasants. Therefore, there is a fear in my mind—I hope, it won't come true—that if this is not done or if the landreforms are not taken up seriously, the green revolution may turn into a red revolution—God forbid, I do not wish that it happens. This is an apprehension in my mind if it is not taken up earnestly, vigorously and expeditiously.

Then, Sir, the related *sine qua non* for the implementation of the projects outlines in the budget is the overhaul in administration. The Prime Minister was the presiding deity of that Commission—the Administrative Reforms Commission; that was some years ago and he presided over the Commission for a year or two and then he became the Deputy Prime Minister. But, he was in touch with the Commission all-through and, therefore, I would like to know how many reports of the Commission have been implemented. I was on that Commission and I know we submitted about 20 reports. The Leader of the Opposition knows about this Commission's reports. He has seen some of the reports in his capacity as the Home Minister at that time. The Commission submitted 20 reports and till 1976, if my memory serves me aright, only 8 or 9 of the reports have been processed or dealt with adequately. The other reports were gathering dust in the shelf, in the almirahs and in the cupboards of the Home Ministry or some other ministries of the Central Government. I would like to know about it. The Prime Minister naturally should be interested in this matter. I hope he will give early thought to this matter of the implementation of the recommendations of the Administrative Reforms Commission. In case they are not to be implemented, the reason should be given as to why they are not to be implemented. That is a very importnt matter so far as administration is concerned because, what we want in this country is an administrative meritorcracy if I may put it that way. And that is the only instrument which can make he Parliamentary democracy work efficiently and effectively. In an administrative meritocracy, the generalists and specialists and all the services work harmoniously and smoothly, and merit is recognised so that there is a smooth symbiosis, that is, living together and working together of the generalists and the specialists and the different services of the administration.

The problem that has bedevilled good administration in this country—apart from inefficiency—has been cor-

[Shri N. K. Shejwalkar]

ruption also, which I am sorry to say the Congress Government promoted and connived at during thirty years of their mis-rule It was with great effort that in the Third Lok Sabha, and earlier also we tried to raise so many issues with regard to corruption which bedevilled the administration but the then Prime Minister at times—unfortunately for the country— put personal friendship above national interest Pandit Jawahar Lal Nehru turned a blind eye and did not take action until in the Third Lok Sabha we succeeded in driving home our charges and get enquiries instituted into the charges against the then Punjab Chief Minister and also a Cabinet Minister here at the Centre

17 hrs.

Mr. Chairman, Sir, the fount of corruption has been at the top It seeps from top to bottom Big bosses in politics, big bureaucrats, big businessmen and big farmers were in collusion and were helping one another during those thirty years of Congress misrule

The Janata Government has started well The Home Minister and the Prime Minister have been emphasising with all the strength at their command that this political corruption and administrative corruption should end and I do hope that vigorous steps will be taken to see that this disease and this malaise which be-devils the administration is eradicated If it cannot be eradicated, it should be minimised very quickly, because otherwise all administration will go to pieces if that is not tackled at the earliest opportunity and ended

The Finance Minister has made various allocations and has been patting himself on the back that he has fulfilled the promises of the Janata Government made during the elections for various things such as electrification, agricultural and allied services, irrigation, flood control, fertilisers, rural electrification, rural roads, etc etc It is good, Sir, electrification also has been included in this. I remember it was Lenin who had said, who coined an epigram or equation, when he was asked about the need for electrification, that Communism is equal to Soviet Russia plus electrification That is the importance he gave to electrification In 1917 Russia was a backward country It was as backward as India is today or perhaps a little more so Therefore, Sir, I am glad this has been given high priority in the Budget

Sir, I would like to refer to another matter and that is the Finance Minister has expressed anxiety with regard to the implementation of projects by State administrations and therefore he proposes to have monitoring cell to watch and keep track of the implementation of the projects by State administrations I do hope that this monitoring cell is not a purely bureaucratic cell Sir, we have establish in this country unfortunately a sort of pseudo-socialisation through nationalisation Nationalisation during the Congress regime had led to Governmentalisation and bureaucratisation It should be, in reality, socialisation Otherwise, it only leads to worse happenings and worse developments, if it is only bureaucratisation and Governmentalisation Then, there is decentralisation That is one of the promises we have made, the Janata Party has made, in our election manifesto I am not for that half-hearted, half-way-house of examining, scrutinising or having a dialogue of, Centre-State relations A demand has been raised in some quarters to examine Centre-State relations and what that demand means in effect is that the State Governments should have more powers State Governments should have more financial powers more administrative powers become very powerful themselves and the Centre should part with its powers But what I am interested in, what I want to emphasise is that this Demand, I will not say a bogus demand is a half-hearted demand, it is a quasi-demand, it is a pseudo demand What is wanted today is decentralisation of

all powers—political, economic, administrative, financial, right from the Centre to the Gram Panchayats, all these levels to the various levels from the Centre. And for that, I would be happy if the Government does appoint an Expert Committee or takes all parties into confidence or the Janata Party itself which constitutes the Government, today has an all-party conference to discuss this matter at leisure, not at too great a leisure but speedily, so that this controversy, unseemy controversy of Centre-State relations, this and that, is not carried on ad nauseum in public. Let us go about it, let us have decentralisation, Mahatma Gandhi himself was for decentralisation. I remember during his last days, in 1944 also, when he was interviewed by an American publicist, John Gunther or somebody else —he was asked "what, Mahatmaji, is your concept of an ideal of a model system for India?" He said in his inimitable style: "I would vest powers in the Gram Panchayat. Let the Village Panchayat have a District Panchayat, the District Panchayat have the Provincial Panchayat or a State Panchayat and then let us have the national Panchayat, what is called the Panchayati Raj". Then the American publicist asked him "Well, Mahatmaji, it sounds very much like the Soviet System. It is very much like Soviet system". And Gandhiji said with his characteristic humility "I do not know much about foreign politics. I have not read about Soviet Russia. I have not read about other foreign countries, but from my own experience, I feel that this is a good system for India, and if it does resemble the Soviet system. Why should we not take something good from whether it is Soviet Russia, whether it is America or whether it is some other country? Why should we not take something good from other countries of the world?" And so it is that he recommended the Panchayati Raj system that has fallen into desuetude or fallen into the doldrums in the last few years. But I am glad that the Janata Government has appointed a Committee recently headed by Shri Ashoka Mehta to scrutinise and examine the achievements or failures of Panchayati Raj institutions in India, and I hope that that enquiry would lead to strengthening the Village Panchayat system as adumbrated in our Constitution. In the Constitution, one of the Directive Principle is as strengthen the Village Panchayat as an organ of our republican system of Government.

Therefore, it is the bounden duty of the government to proceed about this matter also.

Before I close I should like to touch one subject; I do so with considerable trepidation; I do it with some hesitation and that is the issue of prohibition. It has been before the public and it has been in the minds of the nation, of the country during the last so many months. It is true that there is a Directive Principle in the Constitution to that effect, that except for medicinal purposes, intoxicating drinks and drugs should be prohibited. There are so many other Directive Principles also; we have forgotten them. Free compulsory primary education—that has fallen completely into oblivion—and government after government had been the victim of amnesia with regard to that Directive Principle of education.

Be that as it may, even if prohibition is taken up as an issue to be implemented, as a project to be implemented, I for one would not be sorry if Prohibition could be effectively and successfully implemented. The loss of revenue and the heavy expenditure incurred on its implementation would be more than amply compensated by the improvement in the condition of life of the millions addicted to the evil of drink. But the question of question is: can it be effectively and successfully implemented? Here is the Leader of the Opposition; he knew what happened in Bombay during those years of Prohibition. The Prime Minister was himself the Chief Minister of Bombay during those years. I remember, if my memory does not betray me, it came as a shock that in the servant's quarters

[Shri Hari Vishnu Kamath]

of Dr Gilder the then Health Minister in Bombay an illicit distillation plant was discovered.

SHRI K LAKKAPPA (Tumkur) There is no such surprise in the quarters of Shri Raj Narain

SHRI HARI VISHNU KAMATH It came in the papers, it came as a big shock I remember that Turkey tried to introduce Prohibition many years ago and then it was discovered that the Inspector General of Police was himself involved, he was implicated in bootlegging, not himself but through him it was going on and he was involved in the racket of illicit liquor therefore prohibition was given up in hot haste It happened many years ago in the United States also (*An hon Member* Flourishing cottage industry)

The Government have a four year phased programme, that is what they are doing But will this partial prohibition do? Some States have not agreed, Jammu and Kashmir Nagaland have not agreed to introduce Prohibition There is a programme of partial prohibition in some states and in some areas and complete prohibition in other areas It is a complex pattern of wet days, dry days, partially wet days, etc I do not know what the pattern is going to be in Delhi That will lead, I am afraid to more difficulties and more complications to the police and the enforcement staff And the only people who will say Prohibition Zindabad Janata Government Zindabad will be the bootleggers and the enforcement staff Even now I pray to God that prohibition may succeed But if it does not, I do hope that the government will have the moral courage to review the whole thing and see to it that the Bombay farcical, fraud is not repeated on a larger scale through the Central government also I am glad the Leader of the Opposition is smiling; perhaps, it shows his tacit consent He knows the story, inside out of Bombay, Maharashtra of those years, unfortunate years.

Therefore, now, one last word about controls. I know that in a scarce economy there should be controls and you cannot do without control. But it is also necessary to free the people from the red tape of the bureaucracy and also unnecessary controls And, therefore, I would suggest that the Government should appoint what I may call a Controls Commission, to which the Government should approach every three months or six months or one year and convince them of the need for retaining control in any particular commodity, in any particular area or sector because with the experience of the last thirty years that wherever control has been introduced, has been enforced, corruption has become decontrolled That has been our unfortunate experience in the last thirty years

With that I would close for the present I would only like to say in the end that we stand for socialism, Gandhian socialism or democratic socialism firmly founded on moral and spiritual values, which the previous Government completely ignored and cast into the dust We do not want that Our democracy, our socialism must, should, be founded on moral and spiritual values But at the same time let us not try to bamboozle the people by saying that we want socialism, because democracy should be the infrastructure, the base should be democracy Otherwise, Sir,—may I crave your indulgence and the indulgence of the House for repeating an equation which I formulated some years ago—and I still stand-by it—and that is a political equation—socialism minus democracy plus violence is equal to either fascism or communism Socialism minus democracy plus violence organised or unorganised leads us to fascism or communism and that was what Shrimati Indira Gandhi and her cohorts tried to foist on this country

But last year the people successfully resurrected democracy And now Congressmen are repenting, I do not

know whether it is real repentance or crocodile tears, but now they are repenting. Let us leave them to their penitence; let us leave them, I wan't say to let them stew in their own juice, but leave them to their own tears, to their own grief and sorrow and let us hope that they will resolve never to repeat that thing again. To my mind, Sir, fascism and communism are the obverse and reverse of the same coin. That is why I said socialism minus democracy plus violence will lead us to either fascism of communism and therefore, we must avoid both and therefore, we must have democracy, let us first strengthen the base of democracy. Ours is a sovereign democratic republic and we must strengthen our democracy first and see to it that it is founded firmly on moral and spiritual values. If we pay heed to that, all will be well with us Otherwise, I am afraid, worse may befall us

I, therefore, extend to the Budget my criticial support and do hope that the expectations of the Finance Minister will be fulfilled by implementing, by expeditiously implementing all the Plan projects and also by over-hauling the administration, so that the administration is carried on by people who have got a sense of duty and dedication One last word and that is, let the fanatical loyalists—of course, every serviceman is loyal to the Government but there are occasions when one should draw the line—let the fanatical loyalists of the old administration, fanatical loyalists of the old regime, who showed a zeal worthy of a better cause, let them not continue in service. The Government have got powers to retire them, they have got the powers to retire them after 25 years of service. They can retire any serviceman if he does not come up to their expectations And so also the business bosses, the big businessmen who are haunting the corridors of power in Delhi now. Many of them were head over heels in love with the old regime and they tried to derive advantage from that regime. And they now want the same thing from this regime. Let this Government beware of this, lest worse befall this country.

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रायपुर) : वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । इस बजट के लिए मैं उनको बधाई देता हूं । पिछले तीस वर्ष में जहां इस राष्ट्र को कोई दिशा नहीं दी गई थी वहां उन्होंने अपने इस बजट में एक नई दिशा देने का प्रयत्न और प्रयास किया है जिसके लिए वह हार्दिक बधाई के पात्र हैं ।

देश में करोडो व्यक्ति ग्रामीण अंचलों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं । उनकी दृष्टि इस बजट पर थी और वे उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्त मन्त्री बजट मे क्या व्यवस्था करते हैं । इस बजट मे उसकी झलक दिखाई पडती है । मैं निवेदन करना चाहता हू कि जो बातें मैं उठाने जा रहा हूं उनको इस बजट मे जोडने का प्रयास और प्रयत्न होना चाहिये ।

राष्ट्र के सामने आज सबसे भयंकर समस्या विद्युत् का सकट है । यह सकट नही है । इस सकट के निपटने के लिए बजट मे 22 अरब रुपय का आयोजन किया गया है । यह बहुत ही कम है । यदि वास्तव मे हम अपने देश का कल्याण और भला चाहते हैं तो हमें चार फुटिग पर इसके बारे मे निर्णय लेने होंगे । यदि हम बगला देश का बर्डन उठा सकते है तो कोई कारण नही है कि विद्युत् की समस्या का समाधान करने के लिए उसी प्रकार का एक और बर्डन न उठा सकें । इसके लिए चालीस अरब रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये । आने वाले वर्षों मे आप देश को एक नई दिशा देने की बात सोच रहे हैं । तब शायद उसमें आपको सफलता मिल सकती है । अन्यथा इस 22 अरब रुपये से हम उस दिशा में सफल हो सकेंगे, इसमे मुझे शक है ।

कृषि, उद्योग, सिंचाई, व्यापार, रक्षा, जहाजरानी आदि सभी जगहों पर विद्युत् की

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

आवश्यकता पड़ती है । विद्युत् हर स्थान पर अपर्याप्त है । स्थिति यह है कि यदि कृषि के लिए विद्युत् की आवश्यकता पड़ती है तो अर्बन एरियाज के अन्दर कट लगाना हम को पड़ जाता है । इससे सारी इंडस्ट्री चौपट हो जाती है । लघु उद्योगों की स्थिति बहुत भयंकर है । लघु उद्योग धंधे अधर में लटके हुए हैं । कोई नया आदमी लघु उद्योग धंधा लगाने की बात सोच भी नहीं सकता है क्योंकि जो स्थिति है वह अंधकारपूर्ण है जिसका मुकाबला उसको भविष्य में करना पड़ सकता है । इसके डर के मारे उसके पैर ठिठक जाते हैं । मेरा अनुरोध है कि इसकी ओर आप विशेष रूप से ध्यान दें ।

एक और बात को आप देखें । भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज के द्वारा विद्युतीकरण के लिए टरबाइंज बनाए जा रहे हैं । उनकी स्थिति भी बहुत खराब है । उत्तर प्रदेश के अन्दर बारह पावर प्राजैक्ट्स चल रही हैं । उनमें से नौ में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज के टरबाइंज हैं । उन 9 में से अधिकतर रोज बिगड़े रहते हैं । जितनी राज्य सरकार घोषणा करती है उतनी बिजली देने में वह समर्थ नहीं हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इम्पोर्ट किया जाये वह तमाम सामान जो विद्युतीकरण बढ़ाने के लिए आवश्यक है । आज हमारे पास विदेशी मुद्रा है इसलिये टरबाइन्स को और विद्युतीकरण से सम्बन्धित साज सामान को इम्पोर्ट किया जाय ताकि इस संकट को जो कि बिजली का है, दूर किया जा सके । यदि हमने ऐसा कर दिया तो हम अपने देश का कल्याण कर सकेंगे । अन्यथा ईश्वर के भरोसे रह कर अपने देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं । पिछले 30 सालों की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयी है उसको निपटाने के लिये बहुत मेहनत की जरूरत है । लेकिन यदि हमने उतना साज सामान नहीं जुटाया तो हमारी सारी मेहनत बेकार जायेगी ।

कुछेक माननीय सदस्यों ने बजट पर अपने अपने विचार रखे हैं । लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से अपने विचार रखना चाहता हूं क्योंकि पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ गया है जिसका मूल कारण केन्द्रीय सरकार की अवहेलना है । मैं कुछ आंकड़ों के द्वारा वित्त मन्त्री जी को बताना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश संसार के राष्ट्रों में सातवें नम्बर पर आता है जिसकी जनसंख्या 10 करोड़ है । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश को यहां पर एक साधारण प्रदेश की तरह से देखा जाता है, जैसे पंजाब और हरियाणा जो हमारे प्रदेश के सामने केवल 10 वां भाग हैं जो हमारी एक कमिश्नरी में ही समा जायें । और जब अनुदान दिया जाता है तो उसको पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र की तुलना में बांट दी जाती है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो हमारे देश के आंकड़े बताते हैं यू० पी० को 87 करोड़ रु० दिया गया जो कि प्रति व्यक्ति पीछे 14 रु० पड़ा । और उस के मुकाबले में पंजाब में 141 करोड़, वेस्ट बंगाल में 113 करोड़ रु० दिया गया । दूसरी पंच-वर्षीय योजना में यू० पी० को 121 करोड़ रु० दिया गया जो प्रति व्यक्ति पीछे खर्चा पड़ा 18 रु० । पंजाब में 88 करोड़ दिया गया और एक व्यक्ति के पीछे 48 रु० पड़े । इसी तरह से वेस्ट बंगाल को 73 करोड़ रु० दिया गया और वहां एक व्यक्ति पीछे 24 रु० पड़े । परकैपिटा इन्कम जो 1964–65 के अन्दर यू० पी० में 374 रु०, पंजाब में 575 रु०, महाराष्ट्र में 526 रु०, वेस्ट बंगाल में 498 रु० थी । 1975–76 में यू० पी० में 781 रु०, महाराष्ट्र में 1,330 रु०, पंजाब में 1,580 रु०, वेस्ट बंगाल में 1,046 रु० थी । भारत की पर कैपिटा इन्कम 366 रु० और यू० पी० की 250 रु० । यह आंकड़े स्वयं बताते हैं कि उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना इग्नोर किया गया । अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि यू० पी० के प्रधान मन्त्री थे । यदि यू० पी० के प्रधान मन्त्री थे तो यू० पी० की जनता ने बता दिया कि

मुझसे 30 वर्ष तक जो हमारे साथ व्यवहार किया उससे वहां की जनता सन्तुष्ट नहीं है और इसीलिये इस बार वह चुन कर नही आयी ।

पशुधन का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है । 500 करोड रु० का आयोजन केन्द्रीय सरकार ने बजट मे किया है । यह विषय बहुत साधारण सा मालूम पडता है और रुपया बहुत मालूम पडता है । जब कि मेरी दृष्टि मे यह रुपया बहुत नगण्य है । आज संसार के अन्य देशो के मुकाबले मे हमारे देश का दुधारु जानवर डेढ किलो एवरेज दूध देता है, जब कि डेनमार्क, अमरीका, इग्लैंड आदि अन्य देशो के जानवर 20 किलो एवरेज दूध दे रहे हैं । इसी कारण हमारे यहां दुर्गति है । इसकी रोक के लिये हमारे पास कोई पर्याप्त साधन नही है । आज देहात मे दुधारु जानवरो का अभाव हो चुका है । यदि हम वास्तव मे ग्रामीण अचल, पिछडे वर्ग, दरिद्र वर्ग और हरिजनो का कल्याण करना चाहते हैं तो हमे चाहिये कि दरवाजे पर दुधारु जानवर बाध दिये जाये जिससे इन लोगो के जीवन मे एक नई लहर देखने को मिलेगी और कायापलट हो जायगी । दुधारु जानवर केवल इनके परिवार की समस्या का ही समाधान नही करेगे बल्कि अनाज, सब्जी, दाल और तेल वगैरा की समस्या का भी समाधान करेगे । यदि इस पर विस्तार से गहराई से विचार किया जाये तो यह बात बहुत गंभीर है ।

सच्चाई पूछिये तो ओलैम्पिक की हार के बाद पालियामैंट की कमेटी नियुक्त की जाती हैं यह जानने के लिये कि हमारी हाकी की हार का क्या कारण है ? उसकी हार का कारण है हमारी फिजीकल वीकनैस, शारीरिक रूप से हम गिरते जा रहे हैं । हमारे आने वाले बच्चो और पीढी के लिय पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है ।

सचाई यह है कि ओलैम्पिक मे अन्य देश जो हमारी प्रतिस्पर्धा में आते थे जब तक वह हमारी टैक्नीक नहीं जानते थे हमसे हार खाते थे । जैसे ही उन्होने हमारी टैक्नीक सीख ली, जहां हम उन पर पहले 20, 20 गोल करते थे बाद मे 15, 10, 5 और 1 पर आ गये । अब उन्होने हमारे ऊपर गोल करने की बौछार करनी शुरु कर दी है । कारण कि हम फिजीकली वीक हो रहे हैं । हमारे देश मे आज खाने, पीने के सामान का अभाव है । हमारे 80 फीसदी भाई गाव मे रहते है , उनको देने के लिये हमारे पास कुछ नही है ।

हमारा कहना है कि 500 करोड रुपये के स्थान पर हमे इससे दुगनी राशि मिलनी चाहिये और आने वाले 5 वर्षों मे जनता सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि हर घर मे हम दुधारु गाय बधवा देंगे ।

इसके साथ-साथ अगर 5 वर्षों मे हाई ईल्ड वैराइटी देश मे काया पलट सकती है, अगर 10 साल पूर्व की स्थिति पर विचार करे तो एक एकड मे 5 क्विटल गेहू देने वाली वराइटी होती थी जिससे देश मे भुखमरी हो सकती थी लेकिन दुनिया के साइंटिस्टो ने हाई ईल्ड वैराइट की खोज की जिससे 5 क्विटल के स्थान पर 20 क्विटल गेहु पैदा होने लगी और अनाज के मामले मे बहुत कुछ आत्मनिर्भरता हो गई । इसी तरह अगर हम जगह जगह न्यूक्लियस सैंटर खोल दे तो उनमे रिसर्च कर के डेढ किलो दूध देने वाले जानवरो के स्थान पर अधिक दूध देने वाले जानवर तैयार कर सकते है और 2, 4 वर्षों मे धीरे-धीरे भारी मात्रा मे परिवर्तन देखने को मिल सकता है ।

भारत मे साक्षरता 1951 मे 16.6 थी और उत्तर प्रदेश मे 10 8 थी । 1972 मे भारत मे 29.5 हो गई और उत्तर प्रदेश मे यह 21.7 हो गई । इसका मूल कारण उत्तर प्रदेश के पास धन का अभाव था जिससे वह जूझ नहीं सकता था । जब तक उसके पास धन की व्यवस्था नही कराई जायेगी, यह कार्य

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

हो नही सकता । आज उत्तर प्रदेश मे केवल प्राइमरी स्कूलो मे 1 करोड 12 लाख 42 हजार छात्र पढ़ रहे है, इससे पूरा एक देश बन जाता है । जो हमारे बच्चे प्राइमरी म एजूकेशन पा रहे है उस पर 1 अरब 9 करोड रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन हायर एजूकेशन के लिये हमारे पास कुछ नही है । प्राइमरी एजूकेशन की जहा व्यवस्था है, स्कूल बिल्डिंग नही है, टीचर्स नही है तो ऐसी स्थिति मे इस देश का भविष्य क्या होगा, यह मेरी समझ मे नही आता है ।

अगर हमारी एजूकेशन की यही स्थिति हुई तो मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की इन समस्याओ की ओर केन्द्रीय सरकार तुरन्त ध्यान दे और स्पेशल ग्राट की व्यवस्था कर प्रदेश की समस्याओ का समाधान करे ।

अब मैं विद्युत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की स्थिति बताना चाहता हू । भारत की जन-संख्या का 16 फीसदी भाग उत्तर प्रदेश मे है, लेकिन वहा विद्युत का उत्पादन भारत के कुल विद्युत-उत्पादन का 10 फीसदी हो रहा है । महाराष्ट्र, केरल और पजाब हम से कही आगे है । मध्य प्रदेश भी हम से आगे है । इस का दुष्परिणाम यह देखने मे आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से औद्योगीकरण प्राय नगण्य सा हैं । इसकी पुष्टि में आकडो द्वारा करना चाहता हू ।

हमारे प्रदेश मे, जो ससार मे सातवा स्थान रखता है, केवल 5,438 कारखाने हैं । इस का मूल कारण है पैसे का अभाव । पिछले तीस वर्षों मे केन्द्र सरकार द्वारा पब्लिक सैक्टर के उद्योगो की स्थापना पोलीटिकल ग्राउड्ज पर की गई । कुछ महाराष्ट्र मे लगाये गये, तो कुछ कर्नाटक और तामिलनाडु मे लगाये गये । उत्तर प्रदेश मे सफ़ाया ही सफाया नजर आता है । वहा कोई भी भारी उद्योग धधा देखने को नही मिलता है । यह पिछले तीस वर्षों की उत्तर प्रदेश की कहानी है । अगर कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का था, तो मैं कहना चाहता हू कि प्राइम मिनिस्टर ने सारे देश मे अपनी साख बनाने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश मे उसने सदा "दीपक तले अधेरा" वाली स्थिति बना कर रखी ।

हम लोगो ने अपने चुनाव घोषणापत्र मे कहा था कि यदि केन्द्र मे हमारी सरकार बनेगी, तो सेल्ज टैक्स को स्टेट लेवल पर निश्चित रूप से समाप्त कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध मे कुछ दिन पहले प्रधान मत्री और फिनास मिनिस्टर दोनो ने जो उत्तर दिये, उनसे मैं सतुष्ट नही हू । मैं कहना चाहता हूं कि कोई कारण नही है कि प्रदेश सरकारें केन्द्र सरकार के कथनानुसार न चले । आज केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्यो के मुख्य मत्रियो और वित्त मत्रियो को बुलाये और पिछले पाच वर्ष का सेल्ज टैक्स का लेखा जोखा मगा कर देखे कि राज्यो को सेल्ज टैक्स के द्वारा कितनी आय होती है । केन्द्र सरकार यह निर्णय ले कि वह इनडायरेक्ट टैक्सिज को खत्म कर के डायरेक्ट टैक्सिज मे वृद्धि करे—चाहे एक्साइज ड्यूटी कह कर बढाये और चाहे मैनुफैक्चरिग टैक्स कह कर बढाये, और जिस प्रदेश का जितना भाग बनता हो, वह उसे दिया जाये । कोई भी प्रदेश इस मे अनाकानी करने का प्रयास नही करेगा ।

सेल्ज टैक्स के कारण जितना भारी गोलमाल और भ्रष्टाचार देश मे हो रहा है, उतना शायद ही किसी अन्य विभाग मे हो । ईमानदार से ईमानदार आदमी भी अगर दुकान खोल कर बैठता है, तो सेल्ज टैक्स अधिकारी उसको बख्शते नही है । अगर वह ईमानदार बना रहता है, तो दो वर्षों में उसे दकान बन्द करनी पडती है या वह बेईमान हो जाता है । बेईमान तो अधिकतर है, उन्हें हम छोड दें लेकिन ईमानदार भी हमारे देश मे बसते हैं । मैं समझता हू कि

इनडायरेक्ट टैक्सिज को खत्म कर के डायरेक्ट टक्सिज् लगाने से करप्शन खत्म हो जायेगी ।

फ़िनांस मिनिस्टर ने कहा है कि आक्ट्राय को समाप्त कर दिया जायेगा । उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि आक्ट्राय को कब समाप्त किया जायेगा । उस के द्वारा कितनी करप्शन खत्म फैली हुई है । वित्त मंत्री इतनी एक्साइज ड्यूटी लगा दें कि सब टैक्सिज को जोड कर उस की वही माला हो जाये । आज स्थिति यह है कि दिल्ली से मेल्ज टैक्स की चोरी कर के माल बाहर लेजाया जाता है । यू० पी० बार्डर पर मेल्ज टक्स अफसरों के साथ रोज हजारों लाखों रुपयो का गोलमाल हो रहा है । अगर एक आइटम दो रुपये मे बिकता है, तो जो सेल्ज टैक्स की चोरी कर के ले जाता है, वह पौने दो रुपये में बेचता है । इस करप्शन को खत्म करना केन्द्र सरकार का कर्तव्य है ।

जहा तक इनकम टैक्स का सम्बन्ध है, अमरीका और कैनेडा आदि संसार के अन्य राष्ट्र को सामने रखिये । मेरी दृष्टि में शायद वहा की कुल नेशनल इनकम में मक्सिमम योगदान इनकम टैक्स का है, जो डायरेक्ट जनता से लिया जाता है । हमारे देश में पिछले तीस सालों में जनता ने एक काम सीखा है कि इनकम टैक्स किस तरह बचाया जाये, कैसे उस की चोरी की जाये । इस में जनता सफल रही है और हमारे फ़िनांस मिनिस्टर टोटल फ़ेल्युर है । इस समय इनकम टैक्स के माध्यम से तीन प्वाइंट कुछ प्रतिशत टोटल इनकम हो रही है । मेरा निश्चित मत है कि यदि डिपार्टमेंट इस के ऊपर जुट जाए, अपने अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाए, उन के ऊपर विजिलेंस बैठाए तो कोई कारण नहीं है कि हमारी यह इनकम बढ़ कर दुगुनी, तिगुनी न हो जाय । आज इनकम टैक्स इसपैक्टर से लेकर हायर से हायर कमिश्नर तक सब गोलमाल कर रहे है और लाखों, करोड़ों की सम्पत्ति बना रहे हैं, राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं । मैं मिसा के अन्दर जेल में बन्द था । उस समय रामपुर के अन्दर विजलेंस डिपार्टमेंट रेड करने के लिए गया । वह एक धर्मशाला में बैठ गया । जो वहां के बड़े बड़े व्यापारी थे उन सब को बुला लिया गया और उन सब से शेयर मनी कलेक्ट कर के वह चला गया । विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम हो गया । यह स्थिति रही है कांग्रेस रिजीम के अन्दर हमारे इनकम टक्स डिपार्टमेंट की । आज नाम को है पान वाले, सब्जी वाले, फल वाले और इनकम है लाखों रुपये । कोठियां वाले बना कर खड़ी कर रखी हैं, कोई पूछने वाला नही है । कोल्ड ड्रिंक्स आज भी एक रुपये में बिक रहा है । कोका कोला या अन्य जो पेय जल है उन की कीमत तब बढ़ा कर एक रुपया की गई थी जब चीनी 6 रुपये किलो बिक रही थी । आज चीनी का रेट 3 रुपये किलो हो गया है लेकिन फिर भी कम्पा कोला और दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स उसी भाव पर बिक रहे है । कोका कोला एक करोड़ या सवा करोड रुपया गुड विल दिया करता था अमेरिकन कम्पनी को, उस पर भी वह एक रुपये में बिकता था । आज वह भी देने का सवाल नही है और चीनी का भाव भी कम हो गया है फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स वाले दाम घटाने को तैयार नही है और वह आज भी एक रुपये में बिक रहा है । तो इन सब बुराइयों को दूर करने की तरफ ध्यान देना होगा ।

टाफी, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी वाले कितने परसैंट का मार्जिन ले रहे है इस की कल्पना करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुप बैठा है । कोई पूछने वाला नही है । मिठाई वाले 18 रुपये, 20 रुपये किलो मिठाई बेच कर लाखों रुपये का गोलमाल कर रहे है और राष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं । उन को भी कोई देखने वाला नही है ।

सेविंग डिपाजिट्स पर जो इंटरेस्ट घटा दिया है वह छोटे व्यक्ति के साथ अन्याय

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

किया गया है । उस के अन्दर अभी तक हमारे समाज का छोटा और गरीब व्यक्ति ही अपना डिपाजिट करता था । यदि उस के साथ न्याय करना चाहते है तो उस का इंटरेस्ट न घटाएं । बड़ी बड़ी मालदार पार्टियां तो बड़ी बड़ी कम्पनियों के अन्दर ही अपना इन्वेस्टमेंट करती है, स्माल सेविंग्स में उन का इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है ।

हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का भला करेंगे । लेकिन आज हालत क्या है ? अरबन एरियाज के अन्दर हर चीज की व्यवस्था है । कोई रिस्क नहीं है । इंश्योरेंस के माध्यम से हर व्यक्ति सुरक्षित है । रूरल एरियाज में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है । क्राप इंश्योरेंस नहीं है । इस के साथ साथ देशव्यापी सूखा और बाढ़ आती है । देहात आग की लपटों में जल जाते है, कोई उन को बचाने वाला नहीं है । वे दर दर की ठोकरें खाते है । प्रदेश सरकार बहुत काम करती है तो मालगुजारी माफ कर देती है । मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय इसपर गहराई से चिंतन करें । मैं समझता हूं कि हम लोगों को इन समस्याओं से जूझने के लिए अलग से एक फंड बनाना चाहिए जिस में से जो भी परिवार इस प्रकार की कठिनाई में पड़ें उन की सहायता की जा सके । उस के लिए चाहे छोटी मोटी मात्रा में टैक्स भी लगाना पड़े तो वह भी लगाया जाय ताकि उन लोगों के परिवारों को कुछ रुपया दे कर उस विपत्ति से उस समय उन को बचाया जा सके । जैसे इस साल साइक्लोन्स से आंध्र वैगरह में करोड़ों और अरबों रुपये का नुक्सान हुआ, अगर उस प्रकार का एक फंड हो तो उसमें से उन की सहायता कर सकते हैं । इस को चाहे कलेमिटी टैक्स कर के लगाया जाय या किसी और नाम से लगाया जाय लेकिन बहुत कम मात्रा में लगाया जाय । मगर इस तरह का एक फंड होना चाहिए जिस से उन की समस्या का समाधान किया जा सके । मैं वित्त मंत्री को पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नयी दिशा देने की कोशिश की है । तीस साल तक जो एक अन्धकारमय वातावरण था उस को दूर करने में समय लगेगा । मैंने जो विचार दिए हैं मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उन को इस में जोड़ने की कोशिश करेंगे ।

श्री पायस टिर्की (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, यह बजट जो मंत्री महोदय ने सदन में रखा है उस को ध्यान में रखते हुए मैं उन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । देश के बजट का एक फेमिली के बजट के साथ संतुलन है या नहीं, इस को साधारण मनुष्य अनुभव करता है । मुझे संदेह होता है कि इस बजट के द्वारा साधारण मनुष्य विशेष कर हमारे ग्रामों के फेमिली बजट के अंदर एक असंतुलन पैदा हो जायगा । साधारण मनुष्य को क्या चाहिये ? देश की सारी जनता की यही आशा है और वह यही चाहती है कि साधारण मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवा दारू ये पांच चीजें आसानी से मिले इन पांचों का होना मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है । यह हर इन्सान का मौलिक अधिकार है । हमारी जनता सरकार से यह पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें संविधान की मौलिक अधिकार की संज्ञा पावें । परन्तु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट के अन्दर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है । मुझे सन्देह है कि इस बजट के द्वारा साधारण मनुष्य के पास तक मनुष्य की तरह जीवित रहने जैसी मौलिक वस्तुयें पहुंच पायेंगी । ग्रामों में कुटीर उद्योग खोलने की बात कही गई है किन्तु यह बात नहीं कही गई है कि इन कुटीर उद्योगों के मालिक कौन होंगे ? मुझे सन्देह है कि जो जोतदार, जमीनदार, और धनी वर्ग साधारण ग्रामीण लोगों का आज तक शोषण करते आये हैं उन्हीं को दूसरी बार फिर शोषण करने का मौका दिया जा रहा है

कि वे अपना पैसा खर्च करके उद्योग खोलें और शोषण करें । इसलिए हमें देखना होगा कि कुटीर उद्योग के मालिक कौन होंगे ? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है । क्या सरकार अपने अधीन में इन उद्योगों की परिचलना करेगी ।

ये बात कही जाती है कि हमारे देश में अन्न का इतना उत्पादन हुआ है कि उसको गोदाम में रखने के लिए जगह नहीं है । किन्तु आपको मालूम होगा कि अभी भी हमारे देश में 70 परसेन्ट लोग गरीबी की सीमा के नीचे है क्योंकि मुखमरी के कारण इधर उधर घूम रहे है । उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है और शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । जानवरों की तो चिकित्सा उनके मालिकों के जरिये होती है लेकिन इन मनष्यों की चिकित्सा की भी कोई व्यवस्था नहीं है । हम नहीं समझते आजादी में इन्हें कौन सी वस्तु प्राप्त है ।

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में जितने भी उद्योग-धंधे लगाये गए हैं या अभी तक लगाये जा रहे हैं वे मुनाफे के लिए ही लगाये जाते हैं । देश की जरूरत का कोई ध्यान न रखकर किस वस्तु में कितना लाभ होगा इसी को देखते हुए उद्योग धंधे खोले जाते है । चाहे सरकार की ओर से हो या निजी व्यवसायी की ओर से हो । पहले खयाल यही किया जाता है कि उसमें कितना लाभ होगा । यदि सरकार की भी यही नीति रही तो मैं समझता हूं जो बजट पस्तुत किया गया है वह भी विफल रहेगा । कई दफा हमने सुना है कि करीब-करीब बीस हजार करोड़ रुपए का काला धन हमारी अर्थ नीति के समान स्तर रहा है । उसके सबध में इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है । वित्त मंत्री जी ने यह बात नहीं बतलाई है इस काले धन को किस प्रकार बाहर लाया जाये ।

मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि सुरक्षित सोना बेच कर बजट के घाटे को पूरा किया जायेगा । मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मोहम्मद तुगलक ने ऐसा किया था । वह इसलिये कि सभी को खुश करना चाहता था । अगर बड़े लोग नाराज हो गए तो उनको भी खुश करने की गुंजाईश थी और अगर छोटे लोग नाराज हो गए तो उनको भी खुश करने की व्यवस्था थी । कहीं ऐसा न हो कि मोहम्मद तुगलक की अवस्था में हम भी न पहुंच जायें । और सारा देश ही उजाड़ हो जाये । जो पूंजीपति और व्यवसायी मुनाफे के आधार पर उद्योग चला रहे हैं उनका राष्ट्रीयकरण करने की कोई गुंजायश इस बजट में नहीं है । इस बजट पर बहुत आशा रखते हुए भी मुझे कुछ निराशा की झलक दिखाई दे रही है और सन्देह बढ़ रहा है कि इस बजट के द्वारा सम्पन्न लोग और भी सम्पन्न बनेंगे और गरीबों की हालत और भी बदतर हो जायेगी । देश में मुद्रास्फीति यहां तक बढ़ सकती है कि सभाल सकना मुश्किल हो जायेगा । यह तो आगे चल कर ही मालूम होगा कि इस बजट में हर मनुष्य को रोजी, रोटी, मकान, शिक्षा और दवा-दारू मिली है या नहीं । अगर नहीं होती है तो जनता सरकार सफल नहीं होगी ।

हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के चलते मालिकान लोग दूसरों का शोषण करते हैं । इस व्यवस्था में लाभ के लिए मनुष्य का शोषण किया जाता है । गरीब आदमी का शोषण करके ही लाभांश निकाला जाता है । जब सरकार किसी चीज पर टैक्स लगाती है तो बड़े कहलाने वाले लोग उसका भार नहीं सहते हैं, उसका सारा भार साधारण मनुष्य पर चला जाता है । इसके कारण हमारा फैमिली बजट गिरता जा रहा है । साधारण मनुष्य के पास उतना धन नहीं है कि वह अपने फैमिली बजट को सभाल सके । उसके पास जमा पूंजी नहीं है और

[श्री पायस टिर्की]

दूसरे साधन नहीं है। इस बजट में फेमिली बजट में संतुलन रखने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए आज साधारण मनुष्य की दशा दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। साधारण मनुष्य की दशा को सुधारने के लिए हमें वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना जरूरी है।

आजमनुष्य ग्रामीण इलाकों में चौकीदार से लेकर आफिस में बड़े अफसर तक दुर्नीति से ग्रस्त है। कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करने से पहले सोचता है कि उसे तलब के अलावा ऊपर की आमदनी कितनी होगी। जबकि गांव के निरक्षर व्यक्ति यह सोचते हैं कि हम देश की सेवा कैसे करें। वे देश की सेवा करना चाहते हैं। उन्हीं का शोषण किया जाता रहा है। उन्हीं के ऊपर टैक्सों का भार पड़ता है। आज देश में अपना देखो, अपनी गरीबी हटाओ, जिस तरीके से हो वाली नीति चल रही है। जीयो और जीने दो केवल कहावत ही रह गया है। निजी तरक्की ही देश की तरक्की समझी जा रही है। साधारण मनुष्य की स्वार्थ रक्षा के न अब तक कोई कानून बने हैं और न ही उनकी सुनवाई की व्यवस्थाये की गई है। साधारण लोगों के ऊपर जो संकट चला आ रहा है उसका हल इस बजट में नहीं है।

उदाहरण के लिये चाय बागानों के बारे में कहना चाहता हूं। हम चाय बागानों से तीन सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं लेकिन वहां के मजदूरों को कौनसा अधिकार मिला है। वहां के मजदूरों की क्या हालत है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। इस विषय पर सरकार भी निश्चिन्त है। जो लोग देश के लिये इतना लाभ कमा कर देते हैं उनकी हमारी सरकार अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें शिक्षा-दिक्षा, रहन-सहन के, यों कहें कि मनुष्य की तरह से जीने का भी दिये गये है। यदि सरकार घोषणा करती कि मनुष्य को जीने का, भोजन का, मकान का, शिक्षा का, दवा-दारू का मौलिक अधिकार है, फिर सरकार यह घोषणा करती कि अगर कोई भी आदमी भूखा, बेकार, अशिक्षित, नंगा, बेकार, अस्वस्थ है तो थाने में जा कर रिपोर्ट कर सकता है और उसकी सुनवाही होगी तो हर भारतवासी स्वाधीनता का भोग कर पाता। आज उसके लिए थाना, अदालत, स्कूल, कालेज, होस्पिटल सभी के दरवाजे बंद हैं। जिसको पैसा है उसको आजादी है। इसलिए कहता हूं कि इस बजट में साधारण आदमी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी है।

सरकार की नीति है कि देश में पंचायती राज होगा। वैसे तो यह अच्छा प्रतीत होता है। लेकिन मुझे संदेह है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में पंचायती राज कहां तक सफल हो सकेगा। ऐसा न हो कि ग्राम पंचायत धनी वर्ग का गुट बन कर आ जाये और गरीबों के सर्वनाश का कारण बन जाएं।

बस मुझे इतना ही कहना था।

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): Mr. Chairman, Sir. I must first of all thank you for giving me this opportunity to speak on this Budget.

These Budget proposals do not re- first of all thank you for giving me the objectives of the Government. The Budget proposals lack direction in this regard. The Budget proposals will undoubtedly delay the revival of industries, lead to inflation, and slow down investments and decrease the export markets.

The Janata Party in thir election manifesto have told us time and again about this. The hon. Prime Minister, the hon. Home Minister, the hon. Finance Minister and other Ministers

have explained this in so many public meetings. They have said that the rural sector will be given a better deal. They have said that the common people will be given a better deal. But you will be surprised to see that. The general excise duties have been increased from 2 per cent to 5 per cent. There has been a levy on basic excise duties at five per cent, which means, there will be inflation in the market; not only inflation, but the producers will be compelled to increase their prices to a great extent, not to the extent of increased taxes, but due to their cascading effect, the price increases will be quite substantial, as a result of which the people of the country will suffer. There will be less of purchasing power in the hands of the people. Sir, in the Budget, the deficit amount has been increased to Rs. 1050 crores. The public debt has also increased by 15 per cent. This is surprising. There is no well-thought-out plan in the Budget. There are no clear cut objectives. There is no indication of setting up of industries in the rural sector. Unless there are some basic objectives and well-thought-out plans to help the rural sector to grow, nothing can be done. How can the Budget be implemented? I ask the Finance Minister. The hon. Minister of State for Finance is here. Some amount is earmarked for the growth of industries in the rural sector. But there is no proper policy. The last year of the Fifth Five Year Plan has been cancelled.

Sir, they are now depending upon what is called 'The Rolling Plan' which itself is rolling here and there, without any objectives, without any specific proposals, which could be carried on by the people.

Therefore, Mr. Chairman, Sir, the increase in Excise Duties will push up prices of more than 140 commodities. I can cite the names of those commodities which have been published in the newspapers. The hon. Energy Minister is here and I would like to point out to him that at least Rs. 1,000 crores should be provided for electricity generation.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member will continue tomorrow.

---

18 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

EXPANSION OF FOREIGN DRUG COMPANIES.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Prasannabhai Mehta will raise Half-an-Hour Discussion.

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavnagar): Mr. Chairman, Sir, this is not the first time that I am dealing with the subject 'Expansion of Foreign Drug Companies'. I dealt with this subject during the tenure of the Fifth Lok Sabha several times through different means, methods and procedure. I fail to understand why the concerned ministry and its officials who are in this particular section since 10 to 15 years keep a soft corner for the foreign dominated companies who exploit this country by various underhand methods, making fabulous profits and boosting their dividends and reserves on a narrow capital basis.

It is very interesting to know the abnormal rise of the assets within a period of less than two decades. The *Economic Times* New Delhi dated 21st January 1977 has made a mention about the growth of capital reserves and surplus. According to this issue, the assets of twentyfive foreign companies have risen from Rs. 9 crores to more than Rs. 200 crores.

Now the basic question is: how this abnormal and extra-ordinary rise in the assess of foreign companies took place. The principal factor is the connivance of the concerned authorities in allowing them to carry on their commercial activities, that is, their production, in an unlawful manner.

Even at present, the companies like Pfizer, May and Baker, Glaxo, Sandoz,